राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
ईमेल:- info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 12 फरवरी 2026 वर्ष-9,अंक-20 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दीया कुमारी ने पेश किया बजट ....

राजस्थान में फ्री ईलाज, किसानों को सस्ती बिजली

परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी, 8वें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी

स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी भजनलाल सरकार

जयपुर। दीया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी बनेगी। प्रदेश में परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान हुआ है। भजनलाल सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी। जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें भी अब राजस्थान में फ्री इलाज मिलेगा। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 से बढ़ाकर 1.50 लाख किया है। जलप्रदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। साथ ही नई जल नीति लाने का भी ऐलान बजट में किया गया है। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे भी होगा। अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। झींगा पालने वाले किसानों को सस्ती बिजली भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का भी ऐलान किया है।

8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी, दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदना सस्ता, होमगार्ड के 5 हजार पद बढ़ाए

जयपुर।

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज (11 फरवरी) को लगातार तीसरा बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा- 8वें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान किया। सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी। जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें भी अब राजस्थान में फ्री इलाज मिलेगा।

बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख किया है। जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। साथ ही नई जल नीति लाने का भी ऐलान किया गया। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा।इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे भी किया जाएगा।अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी।झींगा पालने वाले किसानों को सस्ती बिजली भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का भी ऐलान किया है। खुरी, जैसलमेर में अल्ट्रा लक्ज़री विशेष पर्यटन क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। कुलधरा में पर्यटकों के लिए सुविधा केंद्र की स्थापना। पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, डिग्गी एवं मंडावा में प्रवेश मार्गों को मॉडल सड़कों के रूप में विकसित करते हुए सौंदर्यीकरण के माध्यम से पर्यटक एवं तीर्थयात्री सुविधाओं हेतु प्रावधान भरतपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से ब्रज कन्वेंशन सेंटर की स्थापना।राज्यभर में चिन्हित बावड़ियों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार (रिस्टोरेशन) के कार्य किए जाएंगे। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत झुंझुनूं, सीकर एवं चूरू जिलों की 660 से अधिक हवेलियों में फसाड इम्प्रूवमेंट, स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे तथा पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने हेतु इच्छुक हवेली मालिकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयास किए जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर एवं बाड़मेर को जोड़ते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित किया जाएगा। झुंझुनूं में वॉर म्यूज़ियम की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ (काठमांडू) सहित अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी तथा 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी।ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होमस्टे संचालकों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सब्सिडी) प्रदान की जाएगी। सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु संभाग स्तर पर लोक नृत्य महोत्सवों का आयोजन किया जाएगा। टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स के कैडर के सौंदर्यीकरण, महिला कर्मियों की तैनाती तथा टूरिस्ट गाइड्स की सुविधाओं के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान। प्रमुख त्योहारों जैसे होली, दीपावली आदि के अवसर पर मंदिरों में सौंदर्यीकरण एवं आरती जैसे आयोजनों हेतु प्रावधान। देवस्थान विभाग की रिक्त भूमि पर बीओटी मॉडल के माध्यम से धर्मशालाओं के विकास हेतु नई नीति बनाई जाएगी। सवाई माधोपुर एवं बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। आंगनबाड़ी और बच्चों के लिए बड़ी सौगात प्रदेश के 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास

लखपति दीदियों को अब मिलेगा 1.5 लाख का लोन

जयपुर ।

राजस्थान सरकार ने महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए एक बार फिर बड़ी योजना की घोषणा की है. राज्य सरकार ने इस बार विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुधार पर जोर दिया है. इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने पुराने प्रावधानों को और मजबूत करते हुए 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल किया है. अब तक लखपति दीदियों को मिलने वाली राशि 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वूमेन बीपीओ स्थापित करने की योजना बना रही है. इसके लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष फंड प्रस्तावित किया गया है. इस योजना के तहत 1,000 महिलाओं को बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो ग्रामीण बैंकों की शाखाओं से सीधे जुड़ेंगी और अन्य महिलाओं को वित्तीय सेवाओं के लिए मार्गदर्शन देंगी। लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को न केवल आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि उन्हें व्यवसायिक कौशल और डिजिटल वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का अवसर भी दिया जा रहा है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने परिवार और समुदाय के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेंगी. राजस्थान सरकार का यह कदम न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए है, बल्कि इसके माध्यम से समाज के वंचित वर्गों, बच्चों और दिव्यांगों के विकास में भी मदद मिल रही है. सरकार का मानना है कि महिला सशक्तिकरण से परिवार और समाज की समग्र प्रगति संभव है. इस योजना से राज्य की ग्रामीण महिलाओं को नई दिशा मिली है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा. लखपति दीदी योजना ग्रामीण राजस्थान में महिलाओं के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो रही है।

युवा, किसान, महिलाओं और ग्रामीणों के लिए ऐतिहासिक बजट- मंत्री मीणा

जयपुर ।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि राज्य का बजट 2026-27 सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को साकार करते हुए विकसित राजस्थान 2047' के विजन को मूर्त रूप देने वाला है। यह बजट प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, आत्मनिर्भर बनाने और अन्नदाता की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट आमजन, कृषक, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से कृषि बजट में इस वर्ष 7.59 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कृषि विकास, कृषक कल्याण और अन्नदाता की आय में वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग, क्षमता विकास, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सुधार की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं।सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार हेतु वर्ष 2030 तक क्षेत्र को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगामी वर्ष लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिस पर 1 हजार 340 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिससे 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

साथ ही 50 हजार सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना पर 1,500 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।उन्नत तकनीक को बढ़ावा देते हुए 200 करोड़ रुपये के अनुदान से 4 हजार किसानों के खेतों पर ग्रीन हाउस, पाली हाउस, शेड नेट, लो टनल और प्लास्टिक मल्च स्थापित किए जाएंगे। उद्यानिकी विकास के तहत औषधीय पौधों, मसाला फसलों, फूलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को साकार करने वाला बजट- जोशी

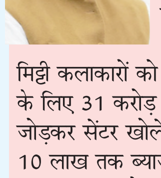

चित्तौड़गढ़ सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार द्वारा वित्त मंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट को जनकल्याणकारी, विकासोन्मुखी एवं दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्व सुखाय, सर्व हिताय की भावना के अनुरूप हर वर्ग का ध्यान रखने वाला सर्वस्पर्शी बजट है। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि बजट में 42 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास, 500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ बनाने, पेयजल परियोजनाओं के लिए 24 हजार करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी करने, एक साल में 3 लाख नए नल कनेक्शन जारी करने, 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ने, 350 करोड़ की लागत से नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने, 15 करोड़ की लागत से मिट्टी कलाकारों को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करवाने, सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री करने, चित्तौड़गढ़ में कुंभा पार्क डेवलप करने के लिए 31 करोड़ की घोषणा हुई है। सांसद सीपी जोशी ने कहा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाने, एआई स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करने, प्रदेश के कॉलेजों में नए संकाय खोलने, सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज/अनुदान दिए जाने, जलवायु नीति और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ के निवेश का रोडमैप तैयार करने, लखपति दीदी योजना में कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख करने, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित महिलाओं को उनके घर के पास ही रोजगार देने के लिए जिला स्तर पर रूरल वूमेन बीपीओ स्थापित करने, प्रदेश की 7,500 आंगनबाड़ियों को आधुनिक नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए 225 करोड़ रूपये का प्रावधान, 17,895 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहली बार बिजली कनेक्शन से जोड़ने, प्रदेश में 220 केवी के 6 नए जीएसएस, 132 केवी के 13 जीएसएस, 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाने की घोषणा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिजली की मॉनिटरिंग करने, 500 स्कूलों में अगले सत्र से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने, टॉयलेस से वंचित सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाने, प्रत्येक जिले में एक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने, 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार करने, स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देने के लिए 323 करोड़ रूपये खर्च की घोषणा, 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे,

थाईलैंड में डे- केयर सेंटर में गोलीबारी, 22 बच्चों समेत 34 की मौत

-हमलावर पूर्व पुलिस अधिकारी बताया जा रहा

बैंकॉक।

थाईलैंड से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। दक्षिणी थाईलैंड में एक डे-केयर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग की घटना में 22 बच्चों समेत कुल 34 लोगों की मौत हो गई। घटना के पीछे एक पूर्व पुलिस अधिकारी का हाथ बताया जा रहा है, जिसने कथित तौर पर डे-केयर सेंटर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी अनुसार, हमलावर ने पहले बच्चों और शिक्षकों को बंधक बनाया और उसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी। मृतकों में बड़ी संख्या में मासूम बच्चे शामिल हैं, जिससे पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक आधिकारिक रूप से मृतकों की कुल संख्या की पुष्टि नहीं की गई है।

हाट याई क्षेत्र में भी गोलीबारी

इसी बीच, दक्षिणी थाईलैंड के हाट याई क्षेत्र से भी गोलीबारी की एक अलग घटना की खबर है। बताया जा रहा है कि वहां एक 18 वर्षीय युवक ने एक स्कूल परिसर में फायरिंग की, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। सोंगखला प्रांत के स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, एक स्कूल में बंदूकधारी द्वारा छात्रों और शिक्षकों को बंधक बनाए जाने की सूचना के बाद पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अभियान शुरू किया। इसी दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस हमलावर की पृष्ठभूमि, हथियार के स्रोत और घटना के पीछे के संभावित कारणों की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या वे अलग-अलग वारदातें हैं।

इस दर्दनाक घटना ने थाईलैंड में स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार की ओर से जल्द आधिकारिक बयान जारी किए जाने की संभावना है।

संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ता ऐतिहासिक बजट-मंत्री

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य की दिशा में ठोस, निर्णायक और परिणामोन्मुखी कदम है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत यह बजट न केवल वित्तीय प्रबंधन का दस्तावेज है, बल्कि यह प्रदेश के सर्वांगीण, समावेशी और संतुलित विकास का स्पष्ट रोडमैप भी है।मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जिस प्रकार सामाजिक न्याय, युवा सशक्तिकरण, महिला उत्थान, किसान कल्याण और गरीब वर्ग के जीवन स्तर में सुधार को बजट के केंद्र में रखा है, वह उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज सवेरा' योजना के माध्यम से प्रदेश को नशामुक्त बनाने का संकल्प हो या घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स' जैसी अभिनव पहल—ये निर्णय समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की सोच को प्रतिबिंबित करते हैं।राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना, युवाओं के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, संभागीय मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले सुविधा तथा जिला मुख्यालयों के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान जैसी घोषणाएं प्रदेश में रोजगार, कौशल, उद्योग और आधारभूत संरचना को नई गति देंगी। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और कानून व्यवस्था जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई घोषणाओं से प्रदेश विकास के उच्चतम शिखर को छू सकेगा। यह बजट मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विकसित राजस्थान-2047 का यह संकल्प केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि जन-जन की आकांक्षाओं को साकार करने का सामूहिक अभियान है। यह ऐतिहासिक बजट आने वाले वर्षों में राजस्थान को आत्मनिर्भर, समृद्ध और अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

यह बजट 'सबका जिक्र, सबकी फिक्र' की भावना से प्रेरित : अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली ।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में केंद्रीय बजट को 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट 'सबका जिक्र, सबकी फिक्र' की भावना से प्रेरित है और देश को तेज गति से प्रगति तथा समृद्धि की ओर ले जाने वाला एक 'डेवलपमेंट एक्सप्रेस' है। सांसद ठाकुर ने कहा कि सरकार ने इस बार समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और आधुनिक विनिर्माण को भी प्राथमिकता दी गई है।

स्काउट व गाइड संगठन युवाओं की सेवा संकल्प से जुड़ी संस्कृति- राज्यपाल

जयपुर ।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि युवा स्वयं के विकास के साथ राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें। उन्होंने स्काउट गाइड संगठन के युवाओं को दृढ़ संकल्प शक्ति और मन बनाकर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को अधिकारों की बजाय राष्ट्र और समाज तथा शिक्षा के प्रति कर्तव्य की भावना को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बागडे राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि स्काउट व गाइड संगठन युवाओं की सेवा संकल्प से जुड़ी संस्कृति से जुड़ा संगठन है। उन्होंने राजस्थान को योद्धाओं की भूमि बताते हुए कहा कि यहां का व्यक्ति शौर्य, वीरता और साहस से जुड़ा है। यहां निरंतर लड़ाइयाँ हुई पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण की भावना रही है। उन्होंने सेना में यहां के सर्वाधिक युवाओं के होने की चर्चा करते हुए स्काउट गाइड से जुड़े युवाओं को अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान किया। उन्होंने आपात काल में स्काउट गाइड की रही भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि वह स्वयं स्काउट संगठन में रहे हैं। यह अनुशासन से जुड़ा युवाओं को प्रेरणा देने वाला संगठन है। समारोह में विधायक दर्शन सिंह और वीरेंद्र सिंह, श्री अखिल शुक्ला ने भी विचार रखें। स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त श्री निरंजन आर्य ने राजस्थान में संगठन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बेरोजगारी भी बढ़ा सकता है खाद्य पदार्थों का आयात

देवेंद्र शर्मा

ऐसे समय में जब घरेलू खेती पहले से ही संत्रास में है, किसानों को मंडियों में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 30 से 40 फीसदी कम दाम मिल रहे हैं, भारत के विशाल बाज़ार को सस्ते और बहुत ज़्यादा सब्सिडी वाले खेती उत्पादों के लिए और खोलने से खेती-बाड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

शेक्सपियर के नाटकों में द्वंद्वात्मक कथानक की तरह, एक बड़ी दुविधा यह है कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। जहां एक ओर अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंस ने भारत के साथ एक बढ़िया व्यापार संधि –'अमेरिकी किसानों के लिए फायदेमंद है'– के लिए अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वाणिज्य मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी अमेरिका के साथ 'ऐतिहासिक संधि' के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और दोहराया है कि यह करते वक्त भारत के संवेदनशील कृषि एवं डेयरी क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है।

क्या यह दोनों लोकतंत्रों के लिए 'परस्पर जीत' वाली स्थिति है या यह जोर-जबरदस्ती और मनमानी का नतीजा है, इसकी पुष्टि तो विवरण से ही हो पाएगी। लेकिन जो बातें सार्वजनिक तौर पर चली हुई हैं, उन्होंने पहले ही देशभर की किसान यूनियनों की रीढ़ में सिहरन की लहर दौड़ा दी है। उनके पास ऐसी चिंता करने के लिए पर्याप्त कारण भी हैं।

ऐसे समय में जब घरेलू खेती पहले से ही संत्रास में है, किसानों को मंडियों में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 30 से 40 फीसदी कम दाम मिल रहे हैं, भारत के विशाल बाज़ार को सस्ते और बहुत ज़्यादा सब्सिडी वाले खेती उत्पादों के लिए और खोलने से खेती-बाड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकी किसानों को पहले से ही हर साल भारी सब्सिडी मिलती है, जो कि तकरीबन 66,314 डॉलर प्रति किसान वार्षिक जितनी है (एग्रीकल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट सर्वे, 2020), यह उन्हें उतार-चढ़ावों से बचाती है। इसके अलावा, अमेरिकी प्रशासन वर्ष 2026 में फार्मर्स ब्रिज असिस्टेंस प्रोग्राम (एफबीए) के तहत किसानों को होने वाले प्रति एकड़ नुकसान की भरपाई हेतु 12 बिलियन डॉलर की मदद उत्पाद भुगतान मद के तहत देने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने इसको 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' का नाम दिया है।

ऐसे में जब अमेरिका भारत व्यापार संधि के विवरण का अभी इंतज़ार है, अमेरिका और भारत, दोनों पक्ष बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। ब्रुक रोलिंस ने तो सोशल मीडिया पर यह तक कह डाला है कि इस समझौते से 'भारत के विशाल बाज़ार को अमेरिकी कृषि उत्पादों का अधिक निर्यात हो पाएगा, जिससे कीमतें ऊपर उठेंगी और ग्रामीण अमेरिका में अधिक नकदी आएगी'। यह कथन मोटे तौर पर व्यापार समझौते की शर्तों के मुताबिक है, जिसका जिक्र ट्विटर पर अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था कि अमेरिका में आयात होने वाले भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50 से घटाकर 18 परसेंट कर दी गई है और भारत में नॉन-टैरिफ बैरियर हटाने के अतिरिक्त अमेरिकी निर्यात पर आयात कर शून्य कर दिया गया जाएगा। इस बीच, भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि यह समझौता किसानों के हितों को 'सुरक्षित' रखने के बाद ही किया गया है।

इन भरोसे के बावजूद, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की खबर ने पहले ही किसान समुदाय को परेशान कर डाला है। भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए, जो कोई अन्य जानकारी देने से बच रही है, कई किसान नेताओं ने शक जताया है कि क्या किसानों के हितों की रक्षा में वास्तव में हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में चेतावनी दी है कि आयात शुल्क शून्य होने से सस्ते आयातित उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी, और इसलिए 12 फरवरी से नए विरोध प्रदर्शनों की धमकी दी है। किसान नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों की तर्ज पर होंगे।

किसान समुदाय को इस बात का भी गुस्सा है कि बजट-2026 में कृषि आय को बढ़ाने के लिए ज़रूरी उपायों पर ज्यादातर चुप्पी रही है, और पहले से ही संकट झेल रहे कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए लाल लकीर कहां खींची जाए, इस पर किसानों से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया है। इसके अलावा, सबसे अमीर व्यापारिक समूह, ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारतीय किसानों को 2000-01 और 2024-25 के बीच कुल मिलाकर 111 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लिहाजा किसानों के लिए एक और बड़ा झटका सहना मुश्किल होगा। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवान संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने चेतावनी दी है 'यह असहाय किसान समुदाय पर बड़े हथौड़े की मार जैसा होगा'।

उन्होंने डर जताया कि यूरोपियन यूनियन और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते की वजह से सेब को जिस स्तर पर भारतीय बाजार में घुसपैठ मिल गई है, वह अभूतपूर्व है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में सेब उद्योग को भय सता रहा है कि उसका अंत व्यवस्थात्मक ढंग से होने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी सेब को शून्य आयात शुल्क पर आने की इजाज़त दी गई, तो पहाड़ी राज्यों की सेब आर्थिकी बर्बाद हो जाएगी। उधर, कपास, सोया और प्याज उगाने वाले किसान पहले से ही कुछ सालों से कम कीमतों से जूझ रहे हैं, और शून्य आयात शुल्क की वजह से बाजार में सस्ती आयातित उत्पाद आने से भारतीय किसानों के फसल के दाम और गिरने की आशंका है। यह स्थिति अंततः उन्हें खेती छोड़ने को मजबूर कर देगी।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति हर साल 500 बिलियन डॉलर मूल्य का अमेरिकन निर्यात होने की बात कह रहे हैं, जिसमें ऊर्जा, तकनीक, कोयला और खेती के अलावा दूसरे क्षेत्र शामिल हैं, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि निर्यात का यह आंकड़ा शायद अगले 5 सालों का है यानी 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका से होने वाले सकल निर्यात में कृषि उत्पाद, डेयरी और उससे जुड़े क्षेत्र ही शामिल होंगे। जबकि, हमारे यहां होने वाले आयात में सबसे बड़ा हिस्सा अनाज, कॉटन, दालें, प्याज़, सोयाबीन और कई तरह की वाइन, शराब, फल, सब्जियां, बादाम और दूसरे मेवों का रहने की उम्मीद है। सूचना के अनुसार, कुछ चीज़ें, मसलन कपास, दालें और प्याज़ में 'कोटा एक्सेस' प्रावधान होगा। लेकिन यह चेतावनी है कि

खाद्य पदार्थ आयात करना बेरोजगारी की आमद जैसा है।

कपास का ही मामला लें। सितंबर और दिसंबर, 2025 के बीच कपास आयात पर 11 फीसदी शुल्क हटाने से सस्ते कपास की आमद हुई, जिससे घरेलू कीमतें गिर गईं। जहां कपड़ा उद्योग कम दाम से खुश था, वहीं किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। तीन महीनों में ही आयात 30 लाख गांठें बढ़ गया और भारतीय कपास का दाम 1,000 रुपये से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गया। इसके अतिरिक्त, चूंकि समझौते के अनुसार नॉन-टैरिफ बैरियर हटाने होंगे, और भारत में इस श्रेणी में आते उत्पादों की संख्या कुछ सौ है, ऐसे में भारत अमेरिकी दूध आयात से उपभोक्ता को कैसे दूर रख पाएगा, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अमेरिकी गायों की खुराक में ब्लड-मील और अन्य मांसाहारी अवयव डाले जाते हैं। असल में, ट्रंप जिस तरह विकासशील देशों के गले से नयी व्यापार व्यवस्था उतार रहे हैं और यूरोपियन यूनियन पर भी नज़र रख रहे हैं, वह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन है। 1995 में यह संस्था बनने के बाद से अमेरिका जो हासिल नहीं कर पाया था, अब उसे बांह मरोड़कर पाने का इंतजाम कर लिया है। दबाव में आकर राष्ट्रों के झुकने से, एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है। 'शक्तिशाली सदा सही होता है' वाली हिमाकत कब तक चलेगी, यह तो वक्त ही बताएगा।

लेखक कृषि एवं खाद्य मामलों के विशेषज्ञ हैं।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति हर साल 500 बिलियन डॉलर मूल्य का अमेरिकन निर्यात होने की बात कह रहे हैं, जिसमें ऊर्जा, तकनीक, कोयला और खेती के अलावा दूसरे क्षेत्र शामिल हैं, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि निर्यात का यह आंकड़ा शायद अगले 5 सालों का है यानी 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका से होने वाले सकल निर्यात में कृषि उत्पाद, डेयरी और उससे जुड़े क्षेत्र ही शामिल होंगे। जबकि, हमारे यहां होने वाले आयात में सबसे बड़ा हिस्सा अनाज, कॉटन, दालें, प्याज़, सोयाबीन और कई तरह की वाइन, शराब, फल, सब्जियां, बादाम और दूसरे मेवों का रहने की उम्मीद है।

संपादकीय

साइबर डकैती पर सख्ती

देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों पर शीर्ष अदालत का सख्त रुख वक्त की जरूरत है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में 54 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल फ्रॉड सीधे-सीधे डकैती है। साइबर ठगी खासकर डिजिटल अरेस्ट के जरिये उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जवाबदेह हितधारकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सीबीआई, बैंकों, आरबीआई की कोताही पर प्रश्न खड़े किए। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इन संस्थाओं ने लोगों के खून-पसीने की कमाई को बचाने के लिये समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाये हैं। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में कतिपय बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट का कहना था कि यह कैसे संभव है कि बैंक अधिकारियों की नाक के नीचे साइबर ठग खाताधारकों का करोड़ों रुपया ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं। कोर्ट ने आशंका जतायी कि इन साइबर ठगी में बैंक अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत हो सकती है। साइबर ठगी को सीधी डकैती की संज्ञा देते हुए अदालत ने कहा कि इस ठगी पर रोक के लिये केंद्र सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी एसओपी तैयार करे। इतना ही नहीं कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अन्य हितधारकों के लिये चार सप्ताह में एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। बैंकों की कारगुजारी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि बैंकों को अहसास होना चाहिए कि वे जनता के पैसों के ट्रस्टी हैं। उन्हें जनता के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई कि आखिर कैसे साइबर ठगी के लाखों केस सामने आ रहे हैं। अकसर सवाल उठाये जाते रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट व अन्य धोखाधड़ी के मामलों में करोड़ों रुपये साइबर अपराधी दूसरे खातों में डाल रहे होते हैं तो बैंक समय पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जबकि बैंकों के पास डेबिट कार्ड को अस्थायी रूप से होल्ड करने का भी अधिकार है। इसमें दो राय नहीं कि बैंकों के पास ऐसा सिस्टम होना जरूरी है, जिसके जरिये निगरानी हो सके कि कैसे किसी के खाते से निकाली गई बड़ी धनराशि जल्दी-जल्दी दूसरे खातों में हस्तांतरित हो रही है। निश्चित तौर पर बैंकों के सुरक्षा सिस्टम को तत्काल ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को रिजर्व बैंक के बाबत टिप्पणी करनी पड़ी कि साइबर ठगी के जरिये जिन खातों से पैसा ठिकाने लगाया जाता है, उस पर संबंधित बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यह सवाल तार्किक है कि अब तक संबंधित बैंक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे हैं? इसमें दो राय नहीं कि यदि बैंक,पुलिस और अन्य एजेंसियां समय रहते तत्काल कार्रवाई करें तो लोगों के खातों में डकैती से हुए नुकसान को कम किया जा सकता है। वैसे एक साल में बाइस लाख साइबर ठगी की शिकायतें सामने आने के बाद कहना कठिन है कि सीबीआई और अन्य एजेंसियां साइबर ठगी के मामलों में तत्काल अंकुश लगा पाएंगी। वक्त की जरूरत है पुलिस व अन्य एजेंसियों को प्रशिक्षित करके इतना सक्षम बनाया जाए कि वे इन अपराधों की संख्या पर रोक लगा सकें। यह तभी संभव है जब देश का गृह मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और टेलीकॉम अथॉरिटी मिलकर इस दिशा में तुरत-फुरत काम करें। इसके लिये जरूरी है कि पूरे देश में यथाशीघ्र एसओपी लागू किया जाए। जिसके लिये शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है।

धर्म, समाज और राष्ट्र की चेतना जगाने वाले स्वामी दयानंद

(लेखक - योगेश कुमार गोयल)

स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती (12 फरवरी) पर विशेष

आर्य समाज के संस्थापक के रूप में वंदनीय महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा में 12 फरवरी 1824 को हुआ था और 12 फरवरी को उनकी जयंती मनाई जाएगी। स्वामी दयानंद ऐसे देशभक्त, समाज सुधारक, मार्गदशक और आधुनिक भारत के महान चिंतक थे, जिन्होंने न केवल ब्रिटिश सत्ता से जमकर लोहा लिया बल्कि अपने कार्यों से समाज को नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान की। 1857 की क्रांति में उनका अमूल्य योगदान था। स्वामी दयानंद का बचपन बहुत अच्छा बीता लेकिन उनके जीवन में घटी एक घटना ने उन्हें इस कदर प्रभावित किया कि वे 21 वर्ष की आयु में ही अपना घर बार छोड़कर आत्मिक एवं धार्मिक सत्य की तलाश में निकल पड़े और एक सन्यासी बन गए। जीवन में ज्ञान की तलाश में वे स्वामी विरजानंद से मिले, जिन्हें अपना गुरु मानकर उन्होंने मथुरा में वैदिक तथा योग शास्त्रों के साथ ज्ञान की प्राप्ति की। 1845 से 1869 तक कुल 25 वर्षों की अपनी वैराग्य यात्रा में उन्होंने कई प्रकार के दैविक क्रियाकलापों के बीच विभिन्न प्रकार के योगों का भी गहन अभ्यास किया।

देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी दयानंद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और 'स्वराज' का नारा उन्होंने ही दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने अपनाया और 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' का नारा दिया। वेदों का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ उनकी महत्ता लोगों तक पहुंचाने तथा समझाने के लिए उन्होंने देशभर में भ्रमण किया। जीवनपर्यन्त वेदों, उपनिषदों का पाठ करने वाले स्वामी जी ने पूरी दुनिया को इस ज्ञान से लाभान्वित किया। उनकी किताब 'सत्यार्थ प्रकाश' आज भी दुनियाभर में अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित हो रही है। वेदों को सर्वोच्च मानने वाले स्वामी दयानन्द ने वेदों का प्रमाण देते हुए हिन्दू समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों का डटकर विरोध किया। जातिवाद, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में उनका योगदान उल्लेखनीय है, इसीलिए उन्हें 'सन्यासी योद्धा' भी कहा जाता है। दलित उद्धार तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने कई आन्दोलन किए। हिन्दू धर्म के अलावा इस्लाम तथा ईसाई धर्म में फैली बुराईयों और अंधविश्वासों का भी उन्होंने जोरदार खंडन किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण, धार्मिक कुरीतियों की रोकथाम तथा वैश्विक एकता के प्रति समर्पित कर दिया। वे आध्यात्मिक क्रांति के संदेशवाहक थे।

स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना मुम्बई के गिरगांव में गुड़ी पड़वा के दिन 10 अप्रैल 1875 को की थी, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के साथ समूचे विश्व को एक साथ जोड़ना था। आर्य समाज के द्वारा उन्होंने दस मूल्य सिद्धांतों पर चलने की सलाह दी। मूर्ति पूजा के अलावा वे जाति विवाह, महिलाओं के प्रति असमानता की भावना, मांस के सेवन, पशुओं की बलि देने, मंदिरों में चढ़ावा देने इत्यादि के सख्त खिलाफ थे और इसके लिए उन्होंने लोगों में जागरुकता पैदा करने के अथक प्रयास किए। अपने 59 वर्ष के जीवनकाल में महर्षि दयानंद ने न सिर्फ देश में व्याप्त बुराईयों के खिलाफ लोगों को जागृत किया बल्कि अपने वैदिक ज्ञान से नवीन प्रकाश को भी देशभर में फैलाया। हालांकि कई लोगों ने उनका जमकर विरोध भी किया लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के तार्किक ज्ञान के समक्ष बड़े-बड़े विद्वानों और पंडितों को भी नतमस्तक होना पड़ा। वे अपने जीवन को पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य, सन्यास तथा कर्म सिद्धांत के चार स्तंभों पर खड़ा मानते थे।

स्वामी दयानंद हिन्दी भाषा के प्रबल समर्थक थे और उनका मत था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक ही भाषा 'हिन्दी' बोली जानी चाहिए। मानव शरीर को नश्वर बताते हुए वह कहते थे कि हमें इस शरीर के जरिये केवल एक अवसर मिला है, स्वयं को साबित करने का कि 'मनुष्यता' और 'आत्मविवेक' क्या है। वे कहा करते थे कि शक्ति किसी अलौकिकता या चमत्कारिता के

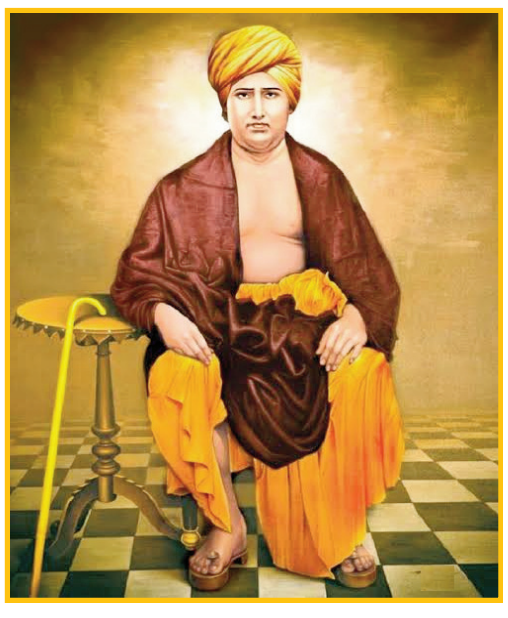

प्रदर्शन के लिए नहीं होती। सभी धर्मों और उनके अनुयायियों को वे एक ही ध्वज तले बैठा देखना चाहते थे। दरअसल उनका मानना था कि आपसी लड़ाई का फायदा सदैव तीसरा उठाता हैं, इसलिए इस भेद को दूर करना आवश्यक है। कर्म करने को लेकर स्वामी जी तर्क देते थे कि काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। वह कहा करते थे कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और तब आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौटकर आएगा। उनका कहना था कि अज्ञानी होना गलत नहीं है लेकिन अज्ञानी बने रहना गलत है।

आध्यात्मिक आकाश का प्रकाश

चिन्मय आकाश में न तो सूर्यप्रकाश की आवश्यकता है, न चन्द्रप्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक- सूर्य, ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के (जिन्हें वैकुण्ठ कहा जाता है) चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्मज्योति कहते हैं। इस तेज का एक अंश महत-तत्व अर्थात जगत से आच्छादित रहता है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन ज्यों ही वह भौतिक जगत रूपी मिथ्या, विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही मुक्त हो जाता है। तब वह यहां वापस लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्णभावनामृत को ग्रहण कर ले, तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्णभावनाभावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए, जो कृष्णभावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है।

उसे भगवद्भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। यहां परमं मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में जगत का कोना-कोना भगवान की सम्पत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और छह ऐयरे से पूर्ण है। कठोपनिषद् में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्यप्रकाश, चन्द्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आन्तरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं।

विचार मंथन

बांग्लादेश चुनाव बाद तय होगी दोस्ती या दुश्मनी

(लेखक - डॉ हिदायत अहमद खान)

बांग्लादेश में अचानक जेन-ज़ी आंदोलन और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटते हुए भारत में शरण लेती हैं। इसके बाद प्रमुख सलाहकार यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता की बागडोर संभालती है और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तोड़ने-मरोड़ने का खेल शुरु हो जाता है। सबसे भरोसेमंद और हितैषी पड़ोसी मित्र देश को दूर करने और दुश्मनों को गले लगाने का काम भी होता है। इस दौरान न हिंसा रुकती है और न ही हालात बदलते हैं। इसी के साथ चुनाव की तारीख भी सामने आ जाती है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का अवसर भर नहीं हैं, बल्कि वे देश की वैचारिक दिशा, लोकतांत्रिक विश्वसनीयता और पड़ोसी देशों खासकर भारत से रिश्तों की जमीन तय करने वाले निर्णायक मोड़ साबित होंगे। कुल 300 सीटों में से 299 सीटों पर मतदान और 'जुलाई चार्टर' पर जनमत संग्रह के साथ यह चुनाव कई स्तरों पर महत्वपूर्ण होने वाले है। बावजूद इसके जिस राजनीतिक माहौल में चुनाव कराए जा रहे हैं, उससे इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर पहले से ही गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति न दिए जाने को लेकर है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली यह पार्टी बांग्लादेश की राजनीति की केंद्रीय धुरी रही है। ऐसे में उसका चुनावी मैदान से बाहर होना लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की आत्मा को कमजोर करता है। अवामी लीग के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ने चुनाव को सुनियोजित बताते हुए निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया को इस तरह से गढ़ा गया है कि एक विशेष विचारधारा को सत्ता में बनाए रखा जा सके। उन्होंने ऐसे चुनाव का बहिष्कार करने की अपील अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक से कर डाली। यहां कहना गलत भी नहीं होगा कि यदि विपक्ष का एक बड़ा दल ही चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वतः संदिग्ध हो जाती है। बहरहाल चुनाव हो रहे हैं ऐसे में जीत-हार के दावे भी सामने आ गए हैं। चुनावी मुकाबला मुख्यतः तारिक रहमान के नेतृत्व वाले बीएनपी गठबंधन और जमात-ए-इस्लामी व नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के 11 दलों के गठबंधन के बीच माना जा रहा है। अनुमानित वोट प्रतिशत बताता है, कि मुकाबला कांटे का है। 13 वर्षों के प्रतिबंध के बाद जमात-ए-इस्लामी का चुनावी मैदान में लौटना भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 2008 के बाद पहली बार वह चुनाव लड़ रही है। खुद को मुख्यधारा की राजनीति में स्थापित करने के प्रयास में जमात ने इस बार एक हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया है, हालांकि किसी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर जमात सुर्खियां भी बटोर रही है। इस मामले में पार्टी का तर्क है कि महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह तर्क समावेशी राजनीति की कसौटी पर अधूरा लगता है। बांग्लादेश के आम चुनाव का एक बड़ा आयाम विदेश नीति भी है। जमात-ए-इस्लामी के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि वे सम्मान और मर्यादा के आधार पर विदेश संबंधों को पुनर्परिभाषित करना चाहते हैं। पिछले 16 वर्षों की विदेश नीति को एक देश अर्थात भारत केंद्रित बताकर उसकी आलोचना की जा रही है। तीस्ता जल बंटवारा, सीमा पर होने वाली घटनाएं और साझा नदियों के पानी का मुद्दा प्रमुख चुनावी विषय बन चुके हैं। यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश में भारत के साथ संबंध अब निर्विवाद नहीं रहे। यदि नई सरकार भारत के प्रति अधिक कठोर रुख अपनाती है, तो द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। सुरक्षा कारण बताकर भारत द्वारा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक न भेजना भी इन्हीं संकेतों की ओर इशारा करता है। यह या तो सतर्क दूरी का संकेत है या फिर आंतरिक परिस्थितियों को लेकर एक प्रकार की प्रतीक्षा की नीति। वैसे यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के लिए बांग्लादेश केवल पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार भी है। सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता, आतंकवाद-रोधी सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी इन सभी पर ढाका की राजनीतिक दिशा का सीधा असर पड़ता है। चिंता का विषय यह भी है कि चुनावी विमर्श में वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ता दिख रहा है। यदि कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती हैं, तो अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द पर प्रश्नचिह्न लग सकते हैं। बांग्लादेश ने पिछले दशक में आर्थिक प्रगति और सामाजिक सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। राजनीतिक अस्थिरता या वैचारिक टकराव इस उपलब्धि को कमजोर कर सकता है। ऐसे में यह चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश के लोकतांत्रिक चरित्र, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और क्षेत्रीय संतुलन की परीक्षा है। नई सरकार यह तय करेगी कि देश सहयोग और संवाद की राह पर चलेगा या टकराव और अविश्वास की ओर मुड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के संबंध इतिहास, भूगोल और साझा संघर्षों से जुड़े हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ढाका में जो भी सत्ता में आए, वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय शांति और सहयोग को प्राथमिकता देगा। क्योंकि अंततः स्थिर, समावेशी और संतुलित बांग्लादेश ही पूरे दक्षिण एशिया के हित में है।

अब ज्यादा भारतीय कृषि उत्पाद होंगे निर्यात, अमेरिकी बाजार में बिना शुल्क मिलेगा प्रवेश

नई दिल्ली। अब भारत अपने कृषि उत्पादों का अमेरिका में ज्यादा निर्यात कर सकेगा। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि निर्यात को बढ़ाने में अमेरिका के साथ कृषि व्यापार के मौजूदा अधिशेष से मदद मिलेगी। भारत का वर्ष 2024 में समुद्री उत्पादों को हटाकर कृषि निर्यात 3.4 अरब डॉलर रहा जबकि आयात 2.1 अरब डॉलर था। भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत को करीब 46 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात बाजार में बिना शुल्क के प्रवेश मिला है। शुल्क-मुक्त उत्पाद का पहले से ही भारत से अमेरिका के आयात में करीब 1.4 अरब डॉलर का हिस्सा हैं। इनमें मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, फल, चाय, कॉफी और जरुरी तेल हैं। भारत को 160 अरब डॉलर के आयात बाजार के लिए 18 फीसदी पारस्परिक शुल्क पर वरीयता पहुंच भी मिलेगी, जो निकट भविष्य में निर्यात की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र को करीब 25 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात बाजार खंड में 18 फीसदी की शुल्क दर पर पहुंच प्राप्त होती है जो विस्तार के लिए अहम अवसर प्रदान करती है।

हॉस्पिटल कंपनी का शेयर 33 फीसदी रिटर्न देगा! अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे शेयर

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार बुधवार को सपाट शुरुआत के साथ खुले। इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑटो स्टॉक्स में बढ़त से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है जबकि रियल्टी और सरकारी बैंकिंग शेयरों में बिकवाली से बाजार में दबाव पड़ा है। इससे पहले मंगलवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। बाजार में ब्रोकरेज हॉउस सिटी ने हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड पर दमदार आउटलुक दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के शेयर फिलहाल अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। ब्रोकरेज हॉउस सिटी ने अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज पर 'बाय' रेटिंग दी हैं। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर 9,600 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इस तरह शेयर 33 फीसदी का रिटर्न दे सकता है। कंपनी के शेयर मंगलवार को 7,220 रुपए पर बंद हुए। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी का कामकाज मजबूत रहा। तीसरी तिमाही में एबिट्डा से पहले की कमाई में क्रमशः 17 फीसदी और 27 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी हुई। आय 6,500 करोड़ रुपए और कमाई 970 करोड़ रुपए रही। ब्रोकरेज ने बताया कि बढ़ोतरी की अगुवाई अस्पताल कारोबार ने की, जहां आय में 15 फीसदी सालाना वृद्धि दर्ज हुई। यह बढ़ोतरी तब हुई जब नई अस्पताल सुविधाएं भी जोड़ी गईं हैं। अस्पताल कारोबार का मार्जिन 60 आधार अंक बढ़कर 24.5 फीसदी हो गया। प्रदर्शन को अपोलो हेल्थको से भी सहारा मिला, जहां अपोलो 24 घंटों के खर्चों में 12 फीसदी सालाना कमी से मार्जिन में 210 आधार अंकों का सुधार हुआ। सिटी ने कहा कि शेयर का वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अपने पुराने औसत स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर एक महीने में करीब 5 फीसदी चढ़ गए हैं। तीन और छह महीने में कंपनी का प्रदर्शन करीब सपाट रहा है। एक साल में स्टॉक ने 20 फीसदी, दो साल में 18 फीसदी और तीन साल में 72.01 फीसदी रिटर्न दिया है। स्टॉक का 52 वीक का हाई 8,099 रुपए और 52 वीक लो 6,002.15 रुपये है। बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप 1,08,899 करोड़ रुपए है।

तीन घंटे के अंदर हटाएं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट, सरकार ने घटाई समयसीमा

एआई का इस्तेमाल कर बनाई गई सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा

नई दिल्ली।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि आगामी 20 फरवरी से सोशल मीडिया और इंटरनेट मध्यवर्ती कंपनियों को दिक्कत देने वाली सामग्री को तीन घंटे के अंदर हटाना होगा। अब तक इसके लिए 36 घंटे का समय दिया जाता था। मध्यवर्तियों को अपने प्लेटफॉर्म से गैर सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों को 24 घंटे के बजाय दो घंटे के अंदर हटाना होगा। मंत्रालय ने इन बदलावों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधनों के रूप में शामिल किया है। यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि मंत्रालय को ऐसे फीडबैक मिले थे कि संवेदनशील सामग्री को हटाने के लिए 24 घंटे और 36 घंटे की अवधि बहुत ज्यादा है जिसके चलते कंटेंट के प्रसार को रोक पाना मुश्किल होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कंपनियों को अब आपत्तिजनक सामग्री को ज्यादा तेजी से हटाना होगा। मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचित ताजा संशोधनों में कहा है कि जो प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को एआई का इस्तेमाल करके सामग्री बनाने की इजाजत देते हैं उन्हें ऐसी सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा कि यह सामग्री कृत्रिम ढंग से तैयार की गई है। ऐसी सामग्री को स्थायी मेटाडेटा या अन्य पहचान के माध्यमों से जोड़ना होगा ताकि ऐसी सामग्री के मूल स्रोत का पता लगाया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि यह कोई भी ऑडियो, दृश्य या ऑडियो-विजुअल जानकारी हो सकती है, जिसे कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके कृत्रिम या एल्गोरिदम से बनाया, उत्पन्न, संशोधित या परिवर्तित किया गया हो, इस प्रकार कि वह वास्तविक, प्रामाणिक या सत्य प्रतीत हो। मंत्रालय ने एआई का इस्तेमाल करके 'सद्भावना' में की गई सामग्री संपादन को इसकी परिभाषा से बाहर रखा है।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया 23पैसे की गिरावट के साथ ही 90.71 रुपये पर बंद हुआ। भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति के बाद से मुद्रा बाजार में उत्साह की बजाय सतर्कता का माहौल बना हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.63 पर खुला। फिर और टूटकर 90.77 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 11 पैसे की गिरावट दिखाता है। रुपया सोमवार को उतार-चढ़ाव भरा कारोबार करते हुए अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.66 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 97.79 पर रहा।

कंपनियों द्वारा आईपीओ, क्यूआईपी और राइट्स इश्यू से जुटाई पर सेबी रखेगी नजर

जानकारी छुपाने, बेजा इस्तेमाल पर उठी चिंताओं पर सख्त नियम बनाने पर विचार

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आईपीओ, पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) और राइट्स इश्यू के जरिए कंपनियों द्वारा जुटाई गई रकम पर निगरानी से जुड़े नियम सख्त बनाने पर विचार कर रहा है। इन माध्यमों से जुटाई गई रकम के इस्तेमाल में देरी, इनकी जानकारी छुपाने और इनके बेजा इस्तेमाल को लेकर उठी चिंताओं के बीच सेबी यह कदम उठाने पर विचार कर रही है। इस मामले से जुड़े लोगों ने इसकी जानकारी दी। फिलहाल जुटाई गई रकम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होने पर कंपनियों को सेबी के पास पंजीकृत एक निगरानी एजेंसी की सेवाएं लेनी पड़ती है। यह आम तौर पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं। सेबी अब यह सीमा घटाकर 50 करोड़ रुपए करने या पूरी तरह हटाने पर विचार कर रहा है। इस कदम से सेबी का निगरानी का दायरा बढ़ जाएगा खासकर छोटे निर्गम भी इसकी जद में आ जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे पर सेबी की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति की पिछली महीने हुई बैठक में चर्चा हुई थी। सेबी को इस मामले पर उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजे गए ई-मेल का समाचार लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया था। यही नहीं, नियामक निगरानी रिपोर्टों से जुड़े खुलासा ढांचे में भी बदलाव करने पर विचार कर रहा है। मौजूदा ढांचे के तहत निगरानी एजेंसियां अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट कंपनी को देती हैं। इसके बाद कंपनियों को यह रिपोर्ट तिमाही समाप्त होने के 45 दिनों के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को सौंपनी होती है। यह पूरा सिलसिला अक्सर बीच में ही अटक जाता है क्योंकि कंपनियां रिपोर्ट सौंपने में देरी करती हैं या इनकी जानकारी नहीं दे पाती हैं। इससे निवेशकों को धन के इस्तेमल पर सीमित जानकारी ही हासिल हो पाती है।

शेयर बाजार सपाट बंद हुआ

सेंसेक्स 40 अंक गिरा, निफ्टी 18 अंक उछला

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को सपाट बंद हुआ। सप्ताह के तीसरे ही कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेतों के बाद भी बाजार में मिला-जुला कारोबार देखा गया। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएससई सेंसेक्स ने एक तय दायरे में कामकाज किया और अंत में यह 40.28 अंक नीचे आकर 84,233.64 पर बंद हुआ। इसी प्रकार 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18.70 अंक की हल्की बढ़त लेकर 25,953.85 पर बंद हुआ। बाजार जानकारों के अनुसार घरेलू शेयर बाजार की नजर तिमाही परिणामों पर लगी है। इसलिए सीमित दायरे में कामकाज हुआ। आज ऑटो और हेल्थ सेक्टर में तेजी रही जबकि आईटी में गिरावट रही। दुनिया भर में बिकवाली के माहौल से भी बाजार पर दबाव पड़ा। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में गिरावट रही।

सेंसेक्स की कंपनियों में टीसीएस के शेयर सबसे ज्यादा 2.46 फीसदी टूटू। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इटरनल, आईटीसी, टेक महिंद्रा, टाइटन और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी गिरे। दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के शेयर उछले। मारुति सुजुकी और ट्रेंट के शेयर भी आज बढ़े।

ब्रोडर मार्केट में निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में बढ़त रही। सेक्टोरल मोर्चे पर निफ्टी हेल्थकेयर सेक्टर में सबसे अधिक 1.62 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। इसके बाद निफ्टी ऑटो में 1.3 फीसदी की वृद्धि हुई। जबकि निफ्टी आईटी सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा। इसमें 1.76 फीसदीत की गिरावट रही। इससे पहले आज सुबह शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ खुला। सुबह सेंसेक्स 84,339 अंक पर खुला। सुबह खुलने के बाद इसमें में तेजी देखने को मिली। सुबह ये की बढ़त के साथ 84,413.21 पर कारोबार कर रहा था।

वहीं इसी तरह निफ्टी सुबह ये 55.75 अंक की फीसदी की बढ़त के साथ ही 25,990.90 पर कामकाज कर रहा था।

वहीं दूनिया भर के बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में सुबह तेजी रही। जापान का निक्केई इंडेक्स बढ़त के साथ उछला। वहीं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के बाजारों में भी बढ़त देखी गई। एशियाई बाजारों की यह बढ़त ऐसे समय में दिखी जब मेरिकी बाजारों में मिश्रित रुख रहा।

अमेरिकी बाजारों में गत दिवस एसएंडपी 500 और नैस्डैक नीचे आया जबकि डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज लगातार तीसरे दिन उछाल के साथ बंद हुआ। अब निवेशकों की नजर अमेरिका के आने वाले लेबर मार्केट डेटा पर टिकी हुई है।

घरेलू बाजार में आज का दिन तिमाही परिणामों के लिए अहम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, डिवीज लैब्स, अशोक लेलैंड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, पतंजलि फूड्स, एसजेवीएन, एस्ट्राजेनेका फार्मा, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, टीबीओ टेक, बायर क्रॉपसाइंस, अमारा राजा एनर्जी, अवंती फीड्स, आईआरकॉन, जुपिटर वैगन्स, पीएंडजी हेल्थ, मिसेज़ बेक्टर्स फूड्स सहित कई कंपनियां आज अपने तीसरी तिमाही के परिणाम घोषित करेंगी।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से फार्मा सेक्टर होगा मजबूत, दोनों देशों को मिलेगा फायदा

सस्ती दवा निर्माण की वजह से अमेरिकी बाजार में अहम सप्लायर बना भारत

नई दिल्ली।

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जहां कई सेक्टरों में अनिश्चितता है, वहीं फार्मा सेक्टर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहा है। कम लेबर कॉस्ट और सस्ती दवा निर्माण क्षमता की वजह से भारत अमेरिकी बाजार के लिए एक अहम सप्लायर बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका की भारत पर निर्भरता पहले से ही मजबूत रही है, जो इस ट्रेड डील के बाद और बढ़ने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जोटा हेल्थकेयर के चेयरमैन ने कहा कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा एफडीए-अप्रूव्ड प्लांट भारत में हैं। भारत से बड़ी मात्रा में जेनरिक दवाएं, लाइफ सेविंग और क्रॉनिक बीमारियों की दवाएं अमेरिका को निर्यात की जाती हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के तहत भारत को एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत मिली है, क्योंकि अब तक टैरिफ के मामलों में अमेरिका शायद ही कभी झुका हो,

लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रोटोकॉल के जरिए संतुलित और लाभकारी समझौता संभव हुआ है। इस डील से दोनों देशों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि भारत से अमेरिका को मुख्य रूप से लाइफस्टाइल और क्रॉनिक बीमारियों से जुड़ी दवाओं का निर्यात होता है। इनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों की दवाएं हैं, जिनकी मांग अमेरिकी बाजार में लगातार रहती है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय संघ के साथ हुई ट्रेड डील से भी भारत को बड़ा फायदा होगा। इस समझौते के तहत एक्सपोर्ट पर ड्यूटी शून्य कर दी गई है। इससे न सिर्फ दवाओं का निर्यात बढ़ेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी और व्यापार का ट्रांसफर भी भारत में होगा। इसके परिणामस्वरूप भारत में दवा निर्माण और सस्ता होगा, जिससे भारतीय मरीजों को भी कम कीमत पर दवाएं मिलेंगी। इस तरह, भारत-यूएस ट्रेड डील और यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौतों से भारतीय फार्मा सेक्टर की वैश्विक पकड़ और मजबूत होने की संभावना है।

नई 7-सीटर निसान ग्रेविटी 17 को लांच करने की तैयारी

नई दिल्ली । भारतीय कार बाजार में 7-सीटर कारों की भारी डिमांड को देखते हुए निसान ग्रेविटी को कंपनी 17 फरवरी को लॉन्च करने वाली है। यह निसान की पहली 7-सीटर एमपीवी होगी और भारतीय बाजार में कंपनी की नई रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। निसान ग्रेविटे रेनो ट्राइबर के सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिससे इसकी कीमत काफी प्रतिस्पर्धी रहने की उम्मीद है। ट्राइबर की शुरुआती कीमत 5.76 लाख रुपये है, और ग्रेविटे भी इसी रेंज में लॉन्च हो सकती है। डिजाइन और रंगों की बात करें तो इसे सिग्नेचर टील शेड के साथ व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और ग्रे विकल्पों में पेश किया जाएगा। पहले जारी किए गए डिजाइन स्केच बताते हैं कि इसमें फ्रंट पर हॉरिजॉन्टल एलईडी डीआरएलएस, क्रोम स्लैट ग्रिल और बोनट पर 'ग्रेविटी' लेटरिंग होगी। पीछे की तरफ स्प्लिट टेल-लैंप और टेलगेट पर हॉरिजॉन्टल इंसर्ट के साथ एक आकर्षक रियर प्रोफाइल मिलेगा। ग्रेविटे में ट्राइबर की तरह 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसमें मैनुअल और एएमटी दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मिलने की संभावना है। निसान ने इसे अपने सिबलिंग ट्राइबर से अधिक बोल्ड और मॉडर्न लुक देने के लिए खास एक्सटीरियर डिजाइन एलिमेंट शामिल किए हैं। उल्टे एल-शेप डीआरएलएस, चौड़ी फ्रंट ग्रिल, सिल्वर बंपर इंसर्ट और कनेक्टेड टेल-लैंप डिजाइन इसे एक प्रीमियम अपील देते हैं।

देश में बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले घटी

यह गिरावट ग्रामीण पुरुष और महिला दोनों के लिए बेरोजगारी दर में कमी के कारण आई

नई दिल्ली।

भारत में 15 साल और उससे ऊपर के लोगों में बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले कमी आई है। यह जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में दी गई। आधिकारिक आंकड़ों में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2025 में घटकर 4 फीसदी हो गई, जो पिछली तिमाही में 4.4 फीसदी थी। यह गिरावट ग्रामीण पुरुष और महिला दोनों के लिए बेरोजगारी दर में कमी के कारण हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल और उससे ज्यादा आयु के शहरी व्यक्तियों की बेरोजगारी दर पिछली तिमाही के 6.9 फीसदी की तुलना में घटकर 6.7 फीसदी हो गई। यह गिरावट शहरी पुरुषों की बेरोजगारी दर में कमी के कारण हुई, जो जुलाई-सितंबर के आंकड़े 6.2 फीसदी से घटकर अक्टूबर-दिसंबर 2025 में 5.9 फीसदी हो गई। अक्टूबर-दिसंबर में 15 साल और उससे ज्यादा आयु के व्यक्तियों की समग्र श्रम बल सहभागिता दर बढ़कर 55.8 फीसदी हो गई, जो पिछली तिमाही के 55.1 फीसदी से ज्यादा है। यह रोजगार में वृद्धि को दर्शाता है।

15 साल और उससे ज्यादा आयु की महिलाओं की एलएफपीआर में अक्टूबर-दिसंबर 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और यह 34.9 फीसदी तक पहुंच गई, जबकि जुलाई-सितंबर 2025 के दौरान यह 33.7 फीसदी थी। रोजगार का एक अन्य सूचक, 15 साल और उससे ज्यादा आयु के व्यक्तियों का श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), जुलाई-सितंबर 2025 में 52.2 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर-दिसंबर 2025 में 53.1 फीसदी हो गया। अप्रैल-जून 2025 से अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान, 15 साल और उससे ज्यादा आयु के व्यक्तियों का ग्रामीण डब्ल्यूपीआर दोनों लिंगों में लगातार बढ़ता रहा। कृषि क्षेत्र ग्रामीण रोजगार में अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रहा, इस तिमाही के दौरान 15 साल और उससे ज्यादा आयु के नियोजित व्यक्तियों में से 58.5 फीसदी कृषि क्षेत्र से संबंधित थे, जो पिछली तिमाही के 57.7 फीसदी से ज्यादा है।

मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर ने तमिलनाडु की प्रसिद्ध मान्ना का किया अधिग्रहण

मुंबई।

मुकेश अंबानी की रिलायंस इडंस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने तमिलनाडु की प्रसिद्ध मान्ना का अधिग्रहण किया है। रिलायंस ग्रुप की तरफ से इसकी जानकारी मंगलवार को दी गई है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो मान्ना के अधिग्रहण के बाद फूड सेगमेंट में और मजबूत हो जाएगा। आरसीपीएल के सेगमेंट में धायम, इंडिपेंड और सिल शामिल है। बता दें आरसीपीएल की मौजूदगी मोटा आनाज आधारित हेल्थ फूड सेगमेंट में बढ़ा है।

बता दें पिछले दो दशक से हेल्ख फोक्सड प्रोडक्ट्स सेगमेंट में मान्ना एक अग्रणी उत्पादक बना हुआ है। रिलायंस इडंस्ट्रीज ने कहा है कि मान्ना की तमिलनाडु सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में काफी मजबूत स्थिति है। बता दें मान्ना का अधिग्रहण ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय ग्राहकों को रुझान मोटा अनाज आधारित भोजन की तरफ बढ़ा है। सरकार भी इसको खूब बढ़ावा दे रही है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के डायरेक्टर कहा कहना है कि तमिलनाडु में मान्ना एक हेल्थ फोकस्ड विश्वसनीय ब्रांड है। कंपनी मोटा आनाज आधारित प्रोडक्ट्स, बेवरेजेज और बेबी फूड्स बेचती है। कंपनी ओट्स, वुमेन्स हेल्थ ड्रींक, आटा प्रोडक्ट बेचती है। इसके अलावा बच्चों के लिए ड्रींक्स, सतुआ से बना ड्रींक जैसे प्रोडक्ट बेच रही है।

बीएलएस कंपनी ने किया अपने शेयरधारकों को 200 फीसदी का डिविडेंड देने का ऐलान

यह फैसला कंपनी की मजबूत आर्थिक स्थिति और बेहतर कैश फ्लो की वजह से लिया

नई दिल्ली। एआई और टेक सेक्टर से जुड़ी कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को 200 फीसदी का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है यानी हर इक्विटी शेयर पर 2 रुपए। कंपनी इस बार कुल 82.35 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर बांटेगी। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा अंतरिम डिविडेंड है। कंपनी के मुताबिक यह फैसला कंपनी की मजबूत आर्थिक स्थिति और बेहतर कैश फ्लो की वजह से लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीएलएस सरकारों और आम लोगों के लिए एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर सर्विस के लिए काम करती है। साथ ही कंपनी फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगातार निवेश कर रही है। कंपनी ने तीसरी तिमाही में जबरदस्त रिजल्ट दिखाया। बीती तिमाही कंपनी का रेवेन्यू 736 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 43.6 फीसदी ज्यादा है। कंपनी ने बिजनेस वीजा और कंसुलर सर्विसेज व डिजिटल सर्विसेज में अच्छी तेजी दिखाई। अगर कंपनी के मुनाफे की बात करें तो बीती तिमाही यह 170 करोड़ रुपए रहा, जहां साल-दर-साल 33.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। बीती तिमाही भी 25.3 फीसदी का उछला आया। कंपनी का कहना है कि ऑपरेशनल कैपेसिटी और खर्चों पर काबू रखने की वजह से मुनाफा अच्छा रहा।

कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि 9 महीनों का परफॉर्मेंस स्थिर और मजबूत रहा। करीब पूरा वित्त वर्ष 2025 का टॉपलाइन और बॉटमलाइन लेवल मैच कर रहा है। खासकर इस तिमाही में दोनों सेगमेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि बीएलएस इंटरनेशनल लगातार नए कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने पाले में कर रही है, वहीं पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिन्यू कर रही है।

उन्होंने कहा कि कंपनी टेक्नोलॉजी से जुड़े नई चीजें तेजी से अपना रही है आधारित नए कदम उठा रही है, जिससे आगे भी बेहतर परिणाम आ सकते हैं।

लोगों के मन में डर और कन्फ्यूजन कम करने सरकार बना रही नया इनकम टैक्स एक्ट

बदलाव अचानक नहीं होंगे, धीरे-धीरे नए सिस्टम की तरफ बढ़ेगा, 1 अप्रैल से होगा लागू

नई दिल्ली।

इनकम टैक्स को लेकर लोगों के मन में डर और कन्फ्यूजन को कम करने की सरकार तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नियम मार्च के पहले हफ्ते में जारी हो सकते हैं। साथ ही नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। बता दें नया इनकम टैक्स एक्ट पहले ही पास हो चुका है, लेकिन आम लोगों के लिए असली तस्वीर इन नियमों से ही साफ होगी। सैलरी पाने वाले कर्मचारियों से लेकर निवेशकों और विदेश से कमाई करने कमाने वालों तक, सभी को इन्हीं नियमों के आधार पर अपने टैक्स की प्लानिंग करनी होगी।

सरकार का दावा है कि बदलाव अचानक नहीं होंगे। धीरे-धीरे नए सिस्टम की तरफ बढ़ा जाएगा, ताकि टैक्सपेयर्स पर बेवजह का दबाव न पड़े। आने वाले नियम तय करेंगे कि टैक्स सिस्टम कितना आसान और पारदर्शी है। नए नियमों के साथ टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। पुराना फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर वाला सिस्टम अब खत्म हो जाएगा। अब 'टैक्स ईयर' की बात होगी, जो आमतौर पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। ये बदलाव धीरे-धीरे आएगा, मतलब पहले कमाए हुए इनकम पर रिटर्न फाइलिंग में कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। सरकार का मकसद साफ-सुथरा और आसान सिस्टम बनाना है। नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, लेकिन पहले साल के रिटर्न बाद में जुलाई 2027 में फाइल होंगे। इससे टैक्सपेयर्स को अचानक बदलाव का बोझ नहीं पड़ेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैलरी पाने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि नए नियमों में पर्क्स यानी नौकरी के साथ मिलने वाले फायदों पर साफ नियम बन रहे हैं। जैसे कि कंपनी की तरफ से फ्री या सस्ता घर, कंपनी कार और ड्राइवर, बिजली-पानी-गैस के बिल, क्लब मेंबरशिप, गिफ्ट्स और वाउचर्स आदि पर टैक्स कैसे लगेगा, ये सब साफ होगा। खास तौर पर गिफ्ट्स और वाउचर्स पर नियम साफ हैं। अगर कर्मचारी की तरफ से साल भर में गिफ्ट, वाउचर या टोकन 15,000 रुपए तक हैं, तो टैक्स नहीं लगेगा। इससे ज्यादा हुआ तो टैक्स लगेगा। पहले ये लिमिट कम थी और काफी कन्फ्यूजन रहता था।

टी20 विश्वकप : नामीबिया के खिलाफ बड़ी जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम गुरूवार को नामीबिया के खिलाफ ग्रुप ए के टी20 विश्वकप मुकाबले में बड़ी जीत के साथ ही लय हासिल करने उतरेगी। भारतीय टीम को अपने पहले ही मैच में अमेरिका के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा था। वहीं इस मैच में उसका लक्ष्य बेहतर प्रदर्शन कर आसान जीत हासिल करना रहेगा। इस बार कमजोर टीमों ने भी सभी को हैरान किया है इसलिए भारतीय इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेगी। भारतीय टीम को इसके बाद पाकिस्तान से भी खेलना है। ऐसे में इस मैच से उसे अभ्यास को भी अच्छा अवसर मिलेगा।

भारतीय टीम को पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ कप्तान सूर्यकुमार यादव की पारी से जीत मिली थी पर इस मैच में सभी अन्य बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। भारतीय टीम के आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तबियत ठीक नहीं है और इस कारण वह इस मैच में नहीं खेलेंगे। ऐसे में ईशान किशन और संजू सैमसन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इसस मैच में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल को भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। गेंदबाजी में भी भारतीय टीम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की इस मैच में वापसी तय है। ऐसे में अलावा मोहम्मद सिराज या अर्शदीप सिंह में से किसी को बाहर बैठना होगा। वहीं दूसरी ओर नामीबिया को शुरू से ही आक्रामक होना होगा और स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, और ऐसी साझेदारी बनानी होगी जिससे वे एक बड़ा स्कोर बना सकें या उसका पीछा कर सकें। उनके गेंदबाजों के लिए भारतीय बल्लेबाजों को रोकना बेहद कठिन हरेगा।

भारत अंतिम ग्यारह

सूर्यकुमार यादव (कप्तान),इशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

सचिन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर बेटे अर्जुन की शादी का निमंत्रण दिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आज अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर उनकी होने वाली बहू सानिया चंडोक भी साथ में थीं। इस मुलाकात की तस्वीरें स्वयं सचिन ने सोशल मीडिया पर साझा कीं हैं।

सचिन ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें जारी करते हुए इसे परिवार के लिए सम्मान की बात बताया। उन्होंने लिखा कि अर्जुन और सानिया की शादी का आमंत्रण प्रधानमंत्री को देकर पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सचिन ने युवा जोड़े के लिए प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और उनकी सलाह के लिए भी आभार जताया। पोस्ट में पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें और अर्जुन-सानिया के साथ एक विशेष तस्वीर भी शामिल थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्जुन और सानिया की शादी से जुड़े कार्यक्रम मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। शादी की रस्में 3 मार्च से शुरू होने की संभावना है, जबकि 5 मार्च को विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। शादी में केवल परिवार के करीबी सदस्य और दोस्त ही शामिल होंगे। समारोह मुंबई में आयोजित किए जाने की चर्चा है। सानिया मुंबई के जाने-माने कारोबारी रवि घई की पोती हैं। सानिया ने अपनी पेशेवर पहचान खुद बनाई है और कारोबार व शिक्षा दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रही हैं। इस दंपत्ति ने पिछले साल अगस्त में बेहद निजी समारोह में सगाई की थी, जिसमें केवल करीबी लोग मौजूद थे। वहीं अर्जुन सचिन तेंदुलकर आईपीएल के अलावा घरेलू क्रिकेट में गोवा से खेलते हैं।

ज़म्पा और एलिस के 'चक्रव्यूह' में फंसा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की 67 रनों से बड़ी जीत

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड पर शानदार जीत दर्ज की और मेहमान टीम को मात्र 115 रनों पर रोककर 67 रनों से विजयी रही। अनुशासित गेंदबाजी और बल्लेबाजों के महत्वपूर्ण योगदान के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से अंत तक मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और अपने अभियान की मजबूत शुरुआत की। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग संभावित रूप से हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण सिर्फ एक रन बनाकर संन्यास ले लिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हैरी टेक्टर तीन गेंदों में शून्य पर आउट हो गए।

तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज नाथन एलिस द्वारा आउट किए जाने के बाद सलामी बल्लेबाज रॉस एडायर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार शुरुआत की और आयरलैंड का स्कोर 13/2 हो गया। कर्टिस कैम्फर (4), बेंजामिन कैलिट्ज़ (2) और गैरेथ डेलानी (11) के विकेट गिरने के बाद आयरलैंड ने जल्दी-जल्दी तीन विकेट गंवा दिए और सातवें ओवर के अंत तक आयरलैंड का स्कोर 43/5 हो गया।

लोरकान टकर और जॉर्ज डॉकरेल ने 46 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, लेकिन 14वें ओवर में एडम ज़म्पा ने टकर को 24 रन पर आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने निचले क्रम के सभी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर 67 रनों से जीत हासिल की और टी20 विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस (4/12) और एडम ज़म्पा (4/23) ने चार-चार विकेट लिए। मैथ्यू कुहनेमैन (1/29) भी विकेट लेने वालों में शामिल थे। इससे पहले, मार्कस स्टोइनिस की जुझारू पारी, जिसमें जोश इंग्लिस और मैट रेनशॉ का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ने ऑस्ट्रेलिया को 182/6 के स्कोर तक पहुँचाया। स्टोइनिस अपनी टीम के लिए 29 गेंदों में 45 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि इंग्लिस और रेनशॉ ने 37-37 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना। हेड और जोश इंग्लिस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत की। हेड पहले ओवर में चौका लगाने के बाद दूसरे ओवर में छह रन बनाकर रन आउट हो गए। पहले ओवर में पांचवीं गेंद पर कैलिट्ज़ ने पॉइंट पर उनका कैच छोड़ दिया था। इंग्लिस और कैमरन ग्रीन ने तेजी से रन बनाना शुरू किया और दोनों ने आयरिश गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। ग्रीन ने 11 गेंदों में 21 रन बनाकर तेज शुरुआत की, लेकिन इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सके क्योंकि पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क एडायर ने मिड-विकेट पर उन्हें आउट कर दिया।

टी20 वर्ल्ड कप: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में हासिल की जीत

-4 रनों से हारा अफगानिस्तान

अहमदाबाद (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका ने यहां हुए बेहद रोमांचक आईसीसी टी20 विश्व कप मुकाबले में अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में चार रनों से हरा दिया। इस प्रकार अफगान टीम जीत के करीब आकर भी उसे हासिल नहीं कर पायी। इस मैच में जीत के लिए मिले 188 रनों का पीछा करते हुए अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन चाहिए थे पर मैच टाई रहा। इसके बाद सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने भी ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर मैच टाई कर दिया। इसके बाद दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 23 रन बजाया जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 19 रन ही बना सकी और मुकाबला मुकाबला हार गयी।

इससे पहले - क्विंटन डिकॉक और रयान रिकल्टन के अर्धशतकों से दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 187 रन बनाए हैं। । इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान एडन मार्करम 8 गेंद पर 5 रन बनाकर शुरुआत में ही फजलहक फारुखी की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद डिकॉक और रिकल्टन ने जबरदस्त बल्लेबाजी कर पारी को संभाला।

डिकॉक और रिकल्टन ने दूसरे विकेट के लिए 114 रन बनाये। इसके बाद अफगान टीम के कप्तान राशिद खान ने डिकॉक और रिकल्टन को एक ही ओवर में आउट कर दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बना दिया।

डिकॉक ने 41 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की सहायता से 59 रन बनाये जबकि रिकल्टन ने 28 गेंद पर 4 छक्कों और 5 चौकों की सहायता से 61 रन बनाये। डेवाल्ड ब्रेविस ने 23 रन बनाये। ट्रिस्टन स्टब्स केवल एक रन ही बना पाये।

डेविड मिलर ने अंत में 15 गेंद पर 20 रन और मार्को जानसेन ने 7 गेंद पर 16 रन बनाकर पारी को 187 तक पहुंचाया।

अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान ने 28 रन देकर 2 विकेट जबकि फजलहक फारुखी ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया। अजमतुल्ला ओमरजाई ने 41 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की ओर से सलामी बल?लोबज रहमानुल्लाह गुरबाज ने अर्धशतक लगाया। गुरबाज ने 84 रन बनायसे। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 4 चौके लगाए। ओपनर इब्राहिम जादरान ने 12 रन लगाए। मध्य क्रम में किसी भी बैटर का बल्ला नहीं चला।

गुलबदीन नायब और सिद्दीकुल्लाह अटल का खाता तक नहीं खुला। दरविश रसूली 15 के स?कोर पर रन आउट हुए। अजमतुल्लाह उमरजई ने 22, मोहम्मद नबी ने 5 और राशिद खान ने 12 गेंदों पर 20 रन जड़े। मुजीब उर रहमान भी बिना कोई रन बनाए वापस लौटे। नूर अहमद ने 9 गेंदों पर 15 रन जड़कर मुकाबले को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। इस दौरान नूर ने 2 सिक्स लगाए।

अभिषेक शर्मा को अस्पताल से मिली छुट्टी

नई दिल्ली ।भारतीय क्रिकेट ओपनर अभिषेक शर्मा को पेट में संक्रमण के कारण दो दिन अस्पताल में रहने के बाद छुट्टी मिल गई है लेकिन नामीबिया के खिलाफ गुरुवार को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच में उनका खेलना अभी तय नहीं है। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने कहा कि अभिषेक के खेलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तिलक वर्मा ने पत्रकारों से कहा, 'अभिषेक को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कल के मैच में उसके खेलने पर फैसला लेने के लिए अभी समय है।अभिषेक अमेरिका के खिलाफ शनिवार को मुंबई में खेले गए पहले मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए थे और इसके बाद उन्होंने मैच में आगे हिस्सा नहीं लिया था। उनकी जगह संजू सैमसन ने फील्डिंग की थी। माना जा रहा है कि मैच के दौरान उनकी तबीयत खराब थी और दिल्ली पहुंचने के बाद और बिगड़ गई।

अर्शदीप नामीबिया के खिलाफ 4 विकेट लेते ही तोड़ देंगे अश्विन का रिकार्ड

नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होने वाले टी20 विश्वकप मुकाबले में एक बड़ा रिकार्ड अपने नाम कर सकते हैं। अर्शदीप इस मैच में अगर चार विकेट लेते हैं तो वह दिग्गज स्पिनर आर अश्विन के भारत की ओर से विश्वकप में सबसे अधिक 32 विकेट लेने का रिकार्ड तोड़ देंगे। अभी अर्शदीप के नाम 29 विकेट हैं। अर्शदीप ने अब तक 15 टी20 विश्व कप मैच खेले हैं, जिनमें 29 विकेट लिए हैं। अर्शदीप ने 2022 में पहली बार टी20 विश्व कप खेला था। इसके बाद 2024 में वह विजेता टीम का हिस्सा रहे और अब अपना तीसरा टी20 विश्व कप खेल रहे हैं। टी20 विश्व कप में भारत के सबसे सफल गेंदबाज अश्विन रहे हैं। अश्विन ने 24 मैचों में 32 विकेट लिए हैं। वहीं ओवरऑल गेंदबाजों की सूची में अर्शदीप 19वें स्थान पर और अश्विन 13वें स्थान पर हैं। साल 2007 से खेले जा रहे टी20 विश्व कप में अभी तक शीर्ष पांच में एक भी भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं है। विश्वकप में भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं। बुमराह ने कुल 26 विकेट लिए हैं।

टी20 विश्व कप बहिष्कार का फैसला बांग्लादेश सरकार का नहीं क्रिकेट बोर्ड का था : नजरुल

ढ़ाका (एजेंसी)। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि टी20 विश्वकप क्रिकेट टूर्नामेंट के बहिष्कार में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी और ये फैसला पूरी तरह से क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने लिया था। इससे पहले बीसीबी ने कहा था कि वह सुरक्षा कारणों से भारत में विश्वकप नहीं खेलेगा। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उसकी जगह पर स्काटलैंड को शामिल कर लिया। तब उस समय कहा जा रहा था कि टी20 विश्व कप में भाग नहीं लेने की बात सरकार ने कही थी और इसलिए बीसीबी ने नहीं खेलने का फैसला किया। वहीं अब खेल सलाहकार के अनुसार ये फैसला क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों का था। उन्होंने राष्ट्र के सम्मान के लिए विश्व कप तक को छोड़ दिया।

वहीं गत माह जनवरी में खिलाड़ियों से मिलने के बाद, नजरुल ने साफ कहा था कि बांग्लादेश के विश्व कप में भाग लेने का फैसला सरकार के रुख पर आधारित रहेगा।

जनवरी में नजरुल ने मीडिया से कहा, 'बैठक का मकसद बस खिलाड़ियों को यह समझाना था कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। मुझे लगता है कि वे समझ गए थे। यही मकसद था और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि हमें आईसीसी से न्याय नहीं मिला। हम विश्व कप में खेलेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से सरकार का फैसला है।'

वहीं अब नजरुल ने कहा, विश्व कप में नही खेलने पर कोई दुख नहीं है। यह फैसला बोर्ड और खिलाड़ियों ने लिया था, क्योंकि उन्होंने देश के क्रिकेट की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और देश की इज्ज़त की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी। आईसीसी ने भी कहा है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगेग और बांग्लादेश को आगे भी मेजबानी मिलेगी। ये हमारे बोर्ड के कड़े रुख की जीत है।

टी20 विश्वकप से बाहर हुए न्यूजीलैंड के ब्रेसवेल, मैककॉनची शामिल

नई दिल्ली ।न्यूजीलैंड के अनुभवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल चोटिल होने के कारण टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हो गए हैं। ब्रेसवेल का बाहर होना कीवी टीम के लिए करारा झटका है क्योंकि वह अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज हैं। ब्रेसवेल के बांए पैर की पिंडली की पुरानी चोट अभ्यास के दौरान उभर आई। जांच में उनकी चोट गंभीर पायी गयी है। विशेषज्ञों के अनुसार उन्हें पूरी तरह फिट होने में तकरीबन तीन सप्ताह का समय लगेगा। ऐसे में वह विश्वकप में नहीं खेल पायेंगे। उनकी जगह पर अब ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर कोल मैककॉनची को टीम में शामिल किया गया है।वह 13 फरवरी को टीम से जुड़ेंगे। ब्रेसवेल को पिछले माह जनवरी में भारत दौरे के समय तीसरे एकदिवसीय के दौरान भी चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पूरा किया था पर वापसी के बाद उनकी चोट फिर उभर आई। उनकी जगह पर शामिल मैककॉनची ने अंतिम बार अप्रैल 2024 में न्यूजीलैंड की ओर से खेला था। घरेलू टी20 सर्किट में उन्होंने 14 विकेट लिए और इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 7.71 रही। मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा हम सभी ब्रेसवेल के लिए दुखी हैं। विश्वकप से बाहर होना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता है। न्यूजीलैंड के लिए खेलना उनके लिए बहुत अहम होता है। उन्होंने वापसी के लिए काफी प्रयास किया पर वह फिर चोटिल हो गए। हम उनके शीघ्र ठीक होने की कामना करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम को 14 फरवरी को ग्रुप डी में अपने तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करना है। अब देखना है कि इसमें मैककॉनची किसने सफल रहते हैं।

मारिन सिलिच 600 जीत हासिल करने वाले बने दूसरे सक्रिय खिलाड़ी बने

डलास । मंगलवार को नेक्सो डलास ओपन में लर्नर टिएन के खिलाफ मिली मारिन सिलिच की 600वीं टूर-लेवल जीत, उनकी कंसिस्टेंसी और लंबे समय तक टिके रहने की झलक है, इन खूबियों ने उन्हें आज के महान खिलाड़ियों में जगह बनाने में मदद की है। एटीपी टूर पर दो दशकों में, जिसका ज़्यादातर हिस्सा 'बिग थ्री' युग में मुकाबला करते हुए बीता, क्रोएशियाई खिलाड़ी न केवल टिका रहा, बल्कि आगे भी बढ़ा है। 37 साल के सिलिच इस खेल के सबसे कड़े कॉम्पिटिटर में से एक हैं, जिनके पास उतनी ही जबरदस्त बेसलाइन फायरपावर है। साथ ही, 21 बार टूर-लेवल टाइटल जीतने वाले सिलिच शांत अंदाज़, आसान मुस्कान और सच्ची दयालुता के बीच संतुलन बनाते हैं, जो खिलाड़ियों और फैंस दोनों को पसंद आता है। सिलिक के नाम सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरी सबसे ज़्यादा जीत हैं, जो सिर्फ़ नोवाक जोकोविच (1,168 और गिनती जारी है) से पीछे हैं। अपनी 600वीं टूर-लेवल जीत हासिल करके, सिलिच अब तक के सबसे ज़्यादा जीत हासिल करने वाले क्रोएशियाई खिलाड़ी बन गए, उन्होंने पूर्व वर्ल्ड नंबर 2 गोरान इवानिसेविच को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अपने शानदार करियर में 599 टूर-लेवल जीत हासिल की थीं। सिलिच के करियर की एक खास बात 2014 में यूएस ओपन में आई, जहां उन्होंने अपनी पहली बड़ी ट्रॉफी उठाई। सिलिच ने फाइनल में जापान के केई निशिकोरी को हराया, इसके कुछ ही पहले उन्होंने सेमीफ़ाइनल में पाँच बार के चैंपियन रोजर फेडरर को हराया था। यह जीत फ़ेडरर के ख़िलाफ़ सिलिच की 11 एटीपी हेड2हेड भिड़ंत में अकेली जीत थी।

सबसे ज्यादा टूर-लेवल जीत प्लेयर जीत (सक्रिय खिलाड़ी)

नोवाक जोकोविच - 1,168, मारिन सिलिच - 600, स्टेन वावरिंका - 586, गाएल मोंफिल्स - 583, अलेक्जेंडर ज्वेरेव - 526

आईसीसी रैंकिंग : अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर कायम, सिकंदर रजा बने नंबर 1 ऑलराउंडर

मुम्बई (एजेंसी)। आईसीसी की ताजा टी20आई रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार है। ओपनर अभिषेक शर्मा बल्लेबाजों की सूची में नंबर 1 स्थान पर बने हुए हैं, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हैं। इस बीच जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने शानदार प्रदर्शन के दम पर टी20आई ऑलराउंडर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच जारी इन रैंकिंग्स ने क्रिकेट जगत में नई चर्चा छेड़ दी है।

बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा का जलवा

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 909 रेटिंग अंकों के साथ टी20आई बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के फिल साल्ट (821), पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (769), इंग्लैंड के जोस बटलर (766) और श्रीलंका के पथुम निसांका (754) को पीछे छोड़ रखा है। रैंकिंग में अन्य खिलाड़ियों ने भी छलांग लगाई है। न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट एक स्थान ऊपर चढ़कर आठवें पायदान पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के कुसल मेंडिस ने छह स्थान की बढ़त लेकर 12वां स्थान हासिल किया। स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुनसे, भारत के ईशान किशन और नीदरलैंड्स के माइकल लेविट ने भी उल्लेखनीय सुधार किया है।

गेंदबाजों की सूची में वरुण चक्रवर्ती आगे

टी20आई गेंदबाजों की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर बने हुए हैं और पाकिस्तान के अबरार अहमद से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। चक्रवर्ती की लगातार प्रभावी गेंदबाजी ने उन्हें नंबर 1 बनाए रखा है। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने एक स्थान ऊपर चढ़कर पांचवां स्थान हासिल किया है और वह टॉप 10 में सबसे बड़ा बदलाव करने वाले गेंदबाज हैं। इसके अलावा, अर्शदीप सिंह (तीन स्थान ऊपर, 11वें), सलमान मिर्जा (नौ स्थान ऊपर, 13वें), ब्रैड इवांस (16 स्थान ऊपर, 15वें), मिशेल सेंटनर (चार स्थान ऊपर, 19वें) और ब्रैडली करी (25 स्थान ऊपर, 24वें) को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है।

सिकंदर रजा बने नंबर 1 टी20आई ऑलराउंडर

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद टी20आई ऑलराउंडर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। कोलंबो में ओमान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रजा ने गेंद और बल्ले दोनों से अहम योगदान दिया। उन्होंने चार ओवर में 1/17 का किफायती स्पेल डाला, जिससे ओमान की टीम सिर्फ 103 रन पर सिमट गई। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए रजा ने विजयी रन बनाकर टीम को आठ विकेट से जीत दिलाई। इस प्रदर्शन की बदौलत उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के सैम अयूब को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि उन्होंने पहली बार पिछले साल के अंत में पाई थी और अब दोबारा नंबर 1 बन गए हैं।

धवन बने दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर

नई दिल्ली । पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि धवन ने दिल्ली सरकार की खेलों के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए स्वयं यह जिम्मेदारी स्वीकार की है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने धवन का आभार जताते हुए दिल्ली के खिलाड़ियों के प्रति उनके योगदान की प्रशंसा की है। दिल्ली सरकार को भरोसा है कि धवन के मार्गदर्शन और प्रेरणा से युवा खिलाड़ियों में नया उत्साह जगेगा और उन्हें नई पहचान मिलेगी। दिल्ली खेल महाकुंभ 13 फरवरी से शुरू होगा। इस दौरान उद्घाटन समारोह से लेकर पूरे आयोजन के दौरान धवन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। धवन ने कहा कि दिल्ली ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अब उसे लौटाने का समय आ गया है। इस कारण वह अपने योगदान के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए अच्छा मंच तैयार किया है जिसमें वह अपना पूरा सहयोग देंगे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

काहिरा में हिंदी सम्मेलन शुरू संस्कृति का सेतु बनी भाषा

काहिरा , एजेंसी। मिस्र की राजधानी काहिरा में रविवार को अफ्रीकी क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। विदेश मंत्रालय की सचिव (दक्षिण) नीना मल्होत्रा ने ऐन शम्स विवि के सहयोग से इस दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की। सम्मेलन का विषय गंगा से नील तक सांस्कृतिक संपर्क और सहयोग रखा गया है। भारतीय राजदूत सुरेश के रेड्डी की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना है।

स्वीडन का भारतीय वायुसेना को ग्रिपेन लड़ाकू विमान देने का प्रस्ताव

स्टॉकहोम, एजेंसी। स्वीडन की रक्षा कंपनी साब (एसएएबी) ने भारतीय वायुसेना को अपने अत्याधुनिक ग्रिपेन-ई लड़ाकू विमान की पेशकश की है। सिंगापुर एयर शो के दौरान कंपनी के उपाध्यक्ष मिकेल फ्रांजेन ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार के समक्ष दुनिया के सबसे उन्नत एयरोस्पेस उद्योग के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इसमें डिजाइन, उत्पादन और रखरखाव के बहुस्तरीय चरण शामिल होंगे। फ्रांजेन ने दावा किया कि ग्रिपेन-ई बाजार में सबसे आधुनिक और लागत प्रभावी विमान है, जो राफेल और तेजस के साथ भारतीय बेड़े में पूरी तरह फिट होगा।

न्यूजीलैंड में 51 मुस्लिमों की हत्या के आरोपी ने दोषसिद्धि को दी चुनौती

क्राइस्टचर्च , एजेंसी। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में 2019 में 51 मुस्लिमों की हत्या करने वाले ब्रेंटन टैरेंट ने अब अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की है। सोमवार को वेलिंगटन की अदालत में उसने दावा किया कि जेल की कठोर परिस्थितियों के कारण वह तर्कहीन हो गया था, जिससे उसे अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह चाहता है कि उसके दोष स्वीकार करने के फैसले को रद्द किया जाए। टैरेंट को बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जिसे वह कम कराना चाहता है।

पी. कुमारन छठे भारत-दक्षिण कोरिया विदेश नीति संवाद की सह-अध्यक्षता करेंगे

सियोल, एजेंसी। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्वी) पी. कुमारन 12 से 13 फरवरी तक दक्षिण कोरिया गणराज्य (आरओके) की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार अपनी यात्रा के दौरान वे दक्षिण कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय की प्रथम उप विदेश मंत्री पार्क यून-जू के साथ छठे विदेश नीति और सुरक्षा संवाद (एफपीएसडी) की सह-अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले 17 जनवरी, 2023 को विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्वी) सौरभ कुमार ने 16-17 जनवरी, 2023 को दक्षिण कोरिया गणराज्य (आरओके) की आधिकारिक यात्रा की, जहां उन्होंने अपने आरओके समकक्ष, विदेश मंत्रालय के प्रथम उप विदेश मंत्री चो ह्युंडोंग के साथ 5वें विदेश नीति और सुरक्षा संवाद (एफपीएसडी) की सह-अध्यक्षता की, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।

कांगो के गांव पर आईएस से जुड़े विद्रोहियों का हमला, 20 लोगों की हत्या

किंशासा, एजेंसी। पूर्वी कांगो में हिंसा की एक और बड़ी घटना सामने आई है। सेना के अनुसार इस्लामिक स्टेट से जुड़े विद्रोही गुट ने एक गांव पर हमला कर कम से कम 20 लोगों की हत्या कर दी। यह हमला सप्ताहांत में नॉर्थ किवु प्रांत के लुबेरो इलाके के मम्बिम्बी-इसिगो गांव में हुआ। हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और बड़ी संख्या में लोग घर छोड़कर भागे हैं। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि हमला एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी एडीएफ गुट ने किया। हमलावरों ने पहले खेतों में काम कर रहे किसानों को निशाना बनाया और फिर गांव में घुसकर चाकू और बंदूक से हमला किया। स्थानीय सामाजिक संगठनों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग अब भी लापता हैं। एडीएफ ने हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। नागरिक समूहों ने इलाके में सेना की कम मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। पूर्वी कांगो में एडीएफ और रवांडा समर्थित एम23 जैसे कई सशस्त्र गुट सक्रिय हैं। एडीएफ ने 2019 में इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा जताई थी और वह अक्सर आम नागरिकों को निशाना बनाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के प्रमुख जीन-पियरे लैक्रोआ ने भी पूर्वी कांगो का दौरा शुरू किया है। इस साल की शुरुआत से ही इस क्षेत्र में एडीएफ हमलों में दर्जनों नागरिक मारे जा चुके हैं। क्षेत्र में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है।

गाजा में फिर गूंजे हवाई हमले, तीन की मौत; इस्राइल बोला- हमने सीजफायर उल्लंघन का दिया जवाब

गाजा पट्टी, एजेंसी। गाजा पट्टी में युद्धविराम के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। इस्राइल के ताजा हवाई हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल सूत्रों ने मौतों की पुष्टि की है। सीजफायर लागू होने के बावजूद हमले और जवाबी कार्रवाई की घटनाएं जारी हैं। इससे इलाके में शांति प्रक्रिया पर नए सवाल खड़े हो गए हैं और हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं।

गाजा सिटी के पश्चिमी इलाके में हुए हमलों के बाद घायलों और मृतकों को शिफा अस्पताल लाया गया। अस्पताल प्रशासन ने तीन लोगों की मौत की जानकारी दी। इस्राइली सेना ने कहा कि उसने रफाह शहर में अपने सैनिकों पर फायरिंग के जवाब में कार्रवाई की। सेना के मुताबिक यह युद्धविराम का उल्लंघन था और जवाब में 'सटीक निशानों' पर हमला किया गया।

युद्धविराम के बावजूद जारी टकराव : करीब चार महीने पहले अमेरिका समर्थित युद्धविराम समझौता लागू हुआ था। यह समझौता हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था। इस योजना को मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावित 20 सूत्रीय ढांचे पर आगे बढ़ाया गया था। समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की अदला-बदली भी हुई। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर झड़पें और सैन्य कार्रवाई पूरी तरह नहीं रुकी।

बंधक समझौता हुआ, पर बड़े मुद्दे बाकी : समझौते के शुरुआती चरण में हमास ने अपने पास मौजूद सभी जीवित बंधकों को रिहा किया। बदले में इस्राइल ने हजारों फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा और कुछ शव भी लौटाए गए। लेकिन गाजा के भविष्य का प्रशासन कौन संभालेगा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी और राजनीतिक ढांचा क्या होगा, जैसे बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। इन सवालों पर अब भी मतभेद बने हुए हैं।

वेस्ट बैंक पर इस्राइली फैसले से यूएन चिंतित : संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस्राइल के वेस्ट बैंक में नियंत्रण बढ़ाने के फैसले पर चिंता जताई है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे कदम दो-राष्ट्र समाधान की संभावना को कमजोर कर सकते हैं। इस्राइल की सुरक्षा कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में नियंत्रण गहरा करने और फलस्तीनी प्राधिकरण की शक्तियां घटाने वाले कदमों को मंजूरी दी है। इस्राइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि इससे फलस्तीनी राज्य की अवधारणा को और कमजोर किया जाएगा।

रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग फिर खुली, पर रफ्तार धीमी : मिस्र से लगने वाला रफाह क्रॉसिंग पॉइंट हाल ही में दोबारा खोला गया है। गाजा प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि आवाजाही की प्रक्रिया अब धीरे-धीरे सुधर रही है। पहले हफ्ते में अव्यवस्था और देरी की शिकायतें आई थीं। यूरोपीय संघ मिशन के अनुसार अब तक सैकड़ों लोग पार कर चुके हैं, जिनमें मेडिकल मरीज भी शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य तंत्र के बुरी तरह प्रभावित होने के कारण करीब 20 हजार लोग इलाज के लिए बाहर जाने की प्रतीक्षा में बताए गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सीजफायर लागू होने के बाद भी सैकड़ों लोगों की मौत दर्ज हुई है। मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले में करीब 1,200 लोग मारे गए थे। इसके बाद इस्राइल की सैन्य कार्रवाई में 72 हजार से अधिक फलस्तीनी मारे जाने का दावा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र और कई स्वतंत्र विशेषज्ञ स्थानीय स्वास्थ्य आंकड़ों को संघर्ष के दौरान सबसे भरोसेमंद स्रोत मानते रहे हैं।

अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ 1% घटाया, कुछ गारमेंट प्रोडक्ट्स पर टैरिफ जीरो करने का वादा भी किया

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ 20% से घटाकर 19% कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने कुछ कपड़ा और गारमेंट उत्पादों पर टैरिफ पूरी तरह खत्म करने का वादा किया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि अमेरिका बांग्लादेशी उत्पादों पर लगाए गए 'रेसिप्रोकल टैरिफ' को 20% से घटाकर 19% कर देगा। ये टैक्स अमेरिका ने व्यापार में असंतुलन और उन तरीकों को लेकर लगाए थे, जिन्हें वह गलत मानता है। पहले अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले सामान पर 37% टैक्स लगाने की घोषणा की थी। बाद में इसे घटाकर 20% किया गया था। अब नए समझौते के बाद यह टैक्स 19% हो जाएगा। बांग्लादेश के कुल निर्यात में कपड़ा और गारमेंट उद्योग की हिस्सेदारी करीब 80% है। यह उद्योग 2024 में हुए छात्र आंदोलन के बाद प्रभावित हुआ था, जिसमें देश की सरकार गिर गई थी। इसके बाद से यह सेक्टर फिर से संभलने की कोशिश कर रहा है। नए समझौते के तहत अमेरिका एक ऐसी सिस्टम बनाएगा, जिससे बांग्लादेश के कुछ कपड़ा और गारमेंट उत्पादों पर जीरो टैरिफ लगेगा। हालांकि यह सुविधा उन्हीं उत्पादों को मिलेगी, जिनमें अमेरिका से भेजा गया कपास या अन्य कच्चा माल इस्तेमाल किया गया होगा। आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में बांग्लादेश ने अमेरिका को 8.4 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि अमेरिका से बांग्लादेश का आयात 2.2 अरब डॉलर रहा।

शबाना महमूद ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं, कश्मीरी मूल की हैं

लंदन, एजेंसी। एपस्टीन फाइल्स विवाद में अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की कुर्सी खतरे में है। लेबर पार्टी ने उनके इस्तीफे की मांग की है। हालांकि स्टार्मर ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच, नए प्रधानमंत्री पद की होड़ में गृह मंत्री शबाना महमूद के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट स्ट्रीटिंग और पूर्व उपप्रधानमंत्री अंगेला रेनर का नाम सामने आ रहा है। शबाना महमूद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर मूल की है। 2025 में गृह मंत्री बनने वाली वह पहली मुस्लिम महिला हैं। अगर वह प्रधानमंत्री बनती हैं, तो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री भी होंगी। ब्रिटेन में एपस्टीन फाइल से जुड़े विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि पीएम स्टार्मर के सबसे भरोसेमंद सहयोगी और डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी को इस्तीफा देना पड़ा।

मैकस्वीनी पर आरोप है कि उन्होंने यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन का समर्थन करने वाले पीटर मंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाकर भेजा था। मैकस्वीनी ने कहा कि यह नियुक्ति गलत थी। मैकस्वीनी ने माना कि उन्हें पता था कि मंडेलसन ने जेफ्री एपस्टीन का जेल जाने के बाद भी समर्थन किया था। मंडेलसन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी रहते हुए एपस्टीन को मार्केट से जुड़ी संवेदनशील जानकारी शेयर की थी। मैकस्वीनी ने कहा कि इस फैसले से पार्टी, देश और राजनीति पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। वहीं विपक्ष का कहना है पीएम स्टार्मर को मामले की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए।

कौन बनेगा बांग्लादेश का प्रधानमंत्री? चुनाव से पहले सर्वे का नतीजा; क्या है भारत विरोधी जमात की हालत

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले माहौल काफी गर्म हैं। इस बार बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें भी चुनाव में पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुआई में अंतरिम सरकार चल रही है। वहीं अब उम्मीद है।

किसके बीच है मुकाबला : इस बार बांग्लादेश में मुख्य मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुआई वाली बीएनपी और कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के बीच है। जमात-ए-इस्लामी का प्रमुख मुद्दा ही अल्पसंख्यकों और भारत के विरोध में रहता है। वहीं बीएनपी का अजेंडा भी भारत के समर्थन में कभी नहीं रहा है।

क्या कहता है चुनाव पूर्व का सर्वे : बांग्लादेश के अखबार प्रथोमोलो ने इस चुनाव को लेकर सर्वे करवाया है। इसके मुताबिक बीएनपी को 200 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तारिक रहमान लंबे समय के बाद ब्रिटेन से बांग्लादेश लौटे है। सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश नेशलिस्ट पार्टी पूर्ण बहुतम मिल सकता है। वहीं भारत विरोधी जमात की हालत बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि वह विपक्ष की भूमिका अदा कर सकता है। जमात-ए-इस्लामी शफीकुर्रहमान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। सर्वे में बताया गया है कि बीएनपी 200 से ज्यादा सीटें जीत सकती है वहीं, जमात-ए-इस्लामी 50 के आसपास सीटें जीत सकता है। बांग्लादेश की जातीय पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। बाकी सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में जाने का अनुमान है। बता दें कि बांग्लादेश की संसद निर्वाचिन के लिए कुल सीटों की संख्या 350 है। 300 सदस्यों को जनता चुनती है और 50 सदस्यों का सीधा निर्वाचन होता है। भारत की तरह बांग्लादेश में भी सांसदों का कार्यकाल पांच साल का होता है। चुनाव के साथ ही जनमत संग्रह भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने देश के लोगों से 12 फरवरी को आम चुनावों के साथ-साथ होने वाले जनमत संग्रह में 'हां' में वोट देने और उनके प्रस्तावित सुधार पैकेज का समर्थन करने की जोरदार अपील की। यूनुस ने सोमवार देर रात वरिष्ठ सचिवों और शीर्ष नौकरशाहों को संबोधित करते हुए कहा, ''यदि जनमत संग्रह के दौरान 'हां' में अधिक वोट मिलते हैं।

सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, साउथ कोरिया में 2 लोगों की मौत

सियोल, एजेंसी। दुनियाभर में प्लेन क्रैश और हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यात्री विमान ही नहीं, सेना के विमान भी हादसों से सुरक्षित नहीं हैं। आज, सोमवार, 9 फरवरी को साउथ कोरिया की सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और प्रशिक्षण उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। यह हादसा साउथ कोरिया के ग्योंग्गी प्रांत के गापेयोंग काउंटी (में हुआ, जब सेना के 15वें एविएशन ग्रुप का एएच-1एस कोबरा हेलीकॉप्टर अटैक बेस से लगभग 800 मीटर दूर एक नदी के किनारे क्रैश हो गया।

2 लोगों की मौत : साउथ कोरिया के ग्योंग्गी प्रांत के गापेयोंग काउंटी में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों लोग (जूनियर वॉरंट ऑफिसर्स थे। हादसे के बाद दोनों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मामले की जांच शुरू : साउथ कोरियाई सेना का हेलीकॉप्टर किस वजह से क्रैश हुआ, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। सेना ने जांच के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम गठित की है, जो यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे की क्या वजह थी। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद आग नहीं लगी और न ही कोई धमाका नहीं हुआ।

एपस्टीन फाइल्स से ब्रिटेन की सरकार पर संकट, पीएम स्टार्मर ने इस्तीफा देने से कर दिया इनकार

लंदन, एजेंसी। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मैंडलसन और यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के संबंधों का खुलासा होने के बाद 19 महीने पुरानी ब्रिटिश सरकार के लिए एक गंभीर संकट पैदा होने के बीच प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने सोमवार को कहा कि वह अपने पद पर बने रहेंगे। अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत रहे पीटर मैंडलसन और अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के संबंधों का खुलासा होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। वह लेबर पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह महज डेढ़ साल के कार्यकाल के बाद उन्हें पद से न हटाए। मैंडलसन को इस उच्च पदस्थ राजनयिक पद पर नियुक्त करने के निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी मध्य-वामपंथी लेबर पार्टी के कुछ सांसदों ने 2024 में पीटर मैंडलसन को राजनयिक नियुक्त करने के उनके फैसले के लिए उनसे इस्तीफा देने का आह्वान किया है। स्कॉटलैंड में लेबर पार्टी के नेता अनस सरवर ने भी प्रधानमंत्री स्टार्मर से इस्तीफा देने की मांग की है।

सरवर ने कहा कि ''ध्यान भटकाने वाली चीजें बंद होनी चाहिए और डाउनिंग स्ट्रीट में नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए।'' ब्रिटेन में डाउनिंग स्ट्रीट पर ही प्रधानमंत्री आवास है। सरवर लेबर पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने स्टार्मर से इस्तीफा देने का आह्वान किया है।

स्टार्मर के चीफ ऑफ स्टाफ और उनके संचार निदेशक ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस बीच, प्रधानमंत्री के कार्यालय ने सोमवार को कहा कि स्टार्मर का पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। स्टार्मर ने संसद में लेबर पार्टी के सांसदों से कहा, ''मैंने आज तक जितने भी संघर्ष किए हैं, उन सबमें जीत हासिल की है।'' उन्होंने कहा, ''मैं अपने जनादेश और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं हूं।'

चीफ ऑफ स्टाफ दे चुके हैं इस्तीफा : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर के 'चीफ ऑफ स्टाफ' ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ संबंधों के बावजूद अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में पीटर मैंडेलसन की नियुक्ति को लेकर विवाद के बीच रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री के 'चीफ ऑफ स्टाफ' मॉर्गन मैकस्वीनी ने कहा कि 2024 में मैंडेलसन को अमेरिका में राजदूत नियुक्त करने का निर्णय 'गलत' था और वह स्टॉर्मर को ऐसा करने की सलाह देने के लिए 'पूरी जिम्मेदारी' लेते हैं।

कनाडा में कर्नाटक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दिनदहाड़े हत्या, गोलियों से कार छलनी

टोरंटो , एजेंसी। कनाडा के टोरंटो शहर में कर्नाटक के रहने वाले 37 साल के एक भारतीय सॉफ्टवेयर पेशेवर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने इस वारदात को शनिवार दोपहर टोरंटो के एक व्यस्त शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट में अंजाम दिया। इससे पूरे भारतीय प्रवासी समुदाय में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान चंदन कुमार राजा नंदकुमार के रूप में हुई है, जो टोरंटो के ग्रेटर टोरंटो एरिया में ब्रैम्पटन का निवासी थे। मूल रूप से वह कर्नाटक के बैंगलोर ग्रामीण जिले के नेलमंगला के पास स्थित थ्यामागोंडलु गांव के रहने वाले थे। चंदन पिछले छह साल से कनाडा में रह रहे थे और एल एंड टी की सहायक कंपनी एलटीआई माइंडट्री में काम कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने बैंगलोर में कॉग्निजेंट के साथ काम किया था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। चंदन अपनी कार के अंदर बैठे थे। तभी हमलावरों ने वुडबाइन शॉपिंग सेंटर के प्रवेश द्वार के पास अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं। टोरंटो पुलिस सेवा के अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचे तो चंदन को कई गोलियां लगी हुई थीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। वारदात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें चंदन की सफेद कार बुलेट के निशानों से छलनी नजर आ रही है।

टोरंटो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे 'टारगेटेड अटैक' माना है। फिलहाल अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। टोरंटो पुलिस सेवा के इंस्पेक्टर एरोल वॉटसन ने कहा, 'यह एक गंभीर घटना है, खासकर एक मॉल में इस तरह की गोलीबारी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। हमारी टीम हत्यारों की तलाश कर रही है। थ्यामागोंडलु गांव में चंदन के माता-पिता अपने इकलौते बेटे की मौत की खबर से पूरी तरह टूट चुके हैं। चंदन के पिता नंदकुमार ने मीडिया को बताया, 'हमने पिछले शुक्रवार को उससे बात की थी। उसने कहा था कि वह इस गर्मी में छुट्टी लेकर घर आएगा। हम उसकी शादी की योजना बना रहे थे। हम पूरी तरह से तबाह हो गए हैं।' परिजनों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि चंदन बार-बार भारत लौटने की योजना टाल रहा था। पिता ने अफसोस जताते हुए कहा, 'अगर उसने हमारी बात मान ली होती और वापस आ गया होता, तो वह आज हमारे साथ होता।

परिवार के कुछ रिश्तेदारों ने चंदन की हत्या के पीछे एक अलग ही आशंका जताई है। परिजनों का मानना है कि चंदन टोरंटो में एक कन्नड़ एसोसिएशन बनाने के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगा हुआ था, जो हत्या का कारण हो सकता है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस संबंध में किसी स्पष्ट मकसद का संकेत नहीं दिया है।

इस घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, 'यह घटना बेहद परेशान करने वाली है। हमने एक कन्नडिगा (कर्नाटक का निवासी) को खो दिया है। हमारे पुलिस विभाग ने पहले ही शव को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय से सहायता मांगी है।' वहीं, चिक्काबल्लापुर के सांसद डॉ. के. सुधाकर ने कहा कि वह विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि चंदन के शव को भारत वापस लाने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। आपको बता दें कि यह टोरंटो में इस साल की तीसरी हत्या है, जिसने कनाडा और कर्नाटक दोनों जगह कन्नडिगा समुदाय के बीच शोक और आक्रोश को जन्म दिया है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

मोहाली में 16 स्कूलों को उड़ाने की धमकी

मोहाली (एजेंसी)। मोहाली के स्कूल-कॉलेजों को बुधवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह करीब साढ़े 7 बजे भेजी मेल में कहा गया कि इनमें दोपहर 1.11 बजे बम ब्लास्ट होगा। इस मेल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी मानव बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके अलावा 13 फरवरी को दोपहर 2.11 बजे नई दिल्ली स्थित संसद में भी बम धमाके की धमकी दी गई है। सुबह 8.50 बजे स्कूल खुलने थे, इससे पहले ही मेल पहुंच गई। जैसे ही धमकी भरी मेल मिली तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद स्कूलों में तत्काल छुट्टी कर दी गई। स्कूल मैनेजमेंट्स ने पेरेंट्स को अर्जेंट मैसेज भेजकर अपने बच्चों को घर ले जाने को कहा। इसके अलावा स्कूल बसों को भी गेट से ही लौटा दिया गया। बच्चों को स्कूल के अंदर एंट्री नहीं दी गई। बम धमकी का पता चलते ही मोहाली पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई। तुरंत बम स्क्वॉड की टीमें लेकर पुलिस फोर्स स्कूलों में पहुंच गई।

असम में भारत का सबसे लंबा भूकंपरोधी पुल तैयार : 100 साल चलेगा

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ने वाला पहला 6-लेन एक्स्ट्राडोसेड ब्रिज या 'महासेतु' बनकर तैयार है। यह पुल न केवल असम बल्कि देश के लिए भी खास है, क्योंकि यह भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्राडोसेड पुल होगा। पुल को भूकंप-रोधी तकनीक से डिजाइन किया गया है और इसकी अनुमानित उम्र 100 वर्ष है। असम का यह क्षेत्र भूकंप जोन-6 में आता है, इसलिए पुल में विशेष पेंडुलम सिस्टम लगाया है, जो भूकंप के झटकों को सहन कर उन्हें नीचे की ओर स्थानांतरित कर देता है। एक्स्ट्राडोसेड पुल गर्डर और केबल दोनों तकनीक पर आधारित होता है। इससे पारंपरिक पुलों की तुलना में ज्यादा मजबूत और किफायती भी होता है। पुल का निर्माण कार्य करीब 99 प्रतिशत पूरा हो गया है। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने इसका उद्घाटन कर सकते है।

फाजिल्का में 17 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या

फाजिल्का (एजेंसी)। फाजिल्का जिले के अबोहर में मलोट रोड पर स्थित एक होटल में 17 साल की लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार, लड़की का शव होटल के कमरे में अर्धनग्न अवस्था में और आंखों पर पट्टी बंधी हुई मिली। उसकी गर्दन तेजधार हथियार से काटी गई थी। होटलकर्मियों ने बताया कि मृतक लड़की आरती अपने प्रेमी सचिन के साथ होटल में आई थी। युवक करीब आधे घंटे बाद खाना ऑर्डर करने का बहाना बनाकर होटल से निकला। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना-1 की पुलिस मौके पर पहुंची और होटल को सील कर सभी रिकॉर्ड, रजिस्टर व अन्य सबूत कब्जे में ले लिए। पुलिस ने सचिन निवासी रामकोट के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आरती मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली थी। उनके पिता कई वर्षों से अबोहर में गौशाला में काम करते हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि आरोपी सचिन पहले भी आरती को परेशान करता था। एसएचओ ने बताया कि आरोपी युवक 22 वर्षीय है और कुई खेड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी संबंधितों से पूछताछ जारी है।

पटना में 60 वर्षीय महिला वकील का झुलसा हुआ शव बरामद

पटना (एजेंसी)। बिहार की राजधानी पटना के कदमकुआं क्षेत्र से दुखद घटना सामने आई है। राजेंद्र नगर रोड नंबर-2 में मौजूद घर से 60 वर्षीय महिला वकील इंदिरा लक्ष्मी का झुलसा हुआ शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इंदिरा लक्ष्मी पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करती थीं। उनके पति रांची में रहते हैं, जबकि उनकी एक बेटी दिल्ली में रहती है। जानकारी के अनुसार, शव घर के बरामदे में जली हुई अवस्था में मिला। घटनास्थल से किरोसिन तेल, माचिस और एक दिया बरामद हुआ है। पुलिस को एक मग में भी केरोसिन तेल मिला है। बताया जा रहा है कि घर का मुख्य दरवाजा बंद था और ताला दोनों तरफ से खुलने वाला था। महिला घर के निचले तले पर अकेली रहती थीं। उनके ऊपर वाले फ्लैट में उनके देवर रहते हैं, जिन्होंने सुबह शव देखा। एक केयरटेकर महिला ने भी महिला जली हुई अवस्था में उन्हें देखा और इसकी सूचना दी। केयरटेकर के अनुसार, रात करीब 12 बजे तक इंदिरा लक्ष्मी बरामदे में बैठी थीं। पुलिस ने बताया कि सूचना सुबह लगभग 7-40 बजे मिली। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया शरीर पर किरोसिन डालकर आग लगाने की आशंका है, हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। घटना से पटना सिविल कोर्ट के वकीलों में शोक की लहर है। अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सहित कई वकीलों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।

एक माह में 800 लोग लापता... चिंतित दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस को दिया नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)। (ईएमएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते गुमशुदगी के मामलों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को नोटिस दे दिया है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लापता व्यक्तियों की लगातार बढ़ती संख्या पर चिंता जताकर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कह दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। याचिका में बताया गया है कि दिल्ली में बीते एक महीने में 800 से अधिक लोगों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। इस बीच जनवरी 2026 के पहले दो हफ्तों में 807 लोगों के लापता होने के मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 807 लापता लोगों में से अब तक 235 का ही पता लग सका है, जबकि 572 लोग अभी भी लापता हैं। इन मामलों में 191 नाबालिग और 616 वयस्क शामिल हैं। इस बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी कर निर्धारित समय में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। किसी व्यक्ति के लापता होने की शिकायत मिलते ही पुलिस के लिए तुरंत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, खासकर यदि मामला नाबालिग से जुड़ा हुआ है।

जन गण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम

-स्कूलों में राष्ट्रगीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई; सिनेमाघरों को छूट

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में 'वंदे मातरम' बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को आई। आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' साथ में गाए या बजाए जाएं, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा।

आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार, राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। अब तक मूल गीत के पहले दो अंतरे ही गाए जाते थे। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है किन-किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जा सकता है, इसकी पूरी लिस्ट देना संभव नहीं है। यह पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। केंद्र इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मना रहा है।

राष्ट्रपति के आगमन और झंडारोहण जैसे कार्यक्रमों में गाया जाएगा

नई गाइडलाइन के अनुसार, तिरंगा फहराने, किसी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों और संबोधनों से पहले और बाद में, और राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। मंत्रियों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी वाले गैर-औपचारिक लेकिन जरूरी कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से गाया जा सकता है, बशर्ते इसे पूरा सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश किया जाए। 10 पेजों के आदेश में, सिविलियन पुरस्कार समारोहों, जैसे कि पद्म पुरस्कार समारोह या ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति उपस्थित हों, वहां भी वन्दे मातरम बजाया जाएगा।

सिनेमा हॉल में लागू नहीं होंगे नए नियम

हालांकि, सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है। यानी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले 'वंदे मातरम' बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं अगर किसी न्यूजरील या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत बजाया जाता है, तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में खड़े होने से प्रदर्शन में व्यवधान और अव्यवस्था हो सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि अब से राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण ही गाया या बजाया जाएगा और इसे सामूहिक गायन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

बेटे सिद्धू मूसे वाला के लिए इंसाफ दिलाने धरने पर बैठे... माता-पिता और छोटा सिद्धू

मानसा (एजेंसी)। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए डीआईजी बठिंडा हरजीत सिंह को मिलने पहुंचे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला की माता चरण कौर और पिता बलकौर सिंह एसएसपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए, तब उनके साथ उनका छोटा सिद्धू भी मौजूद था। सिंह का आरोप था कि उन्होंने साल 2025 के दौरान डीजीपी को सिद्धू मूसे वाला कत्ल मामले में शामिल तीन लोगों के नाम की लिस्ट देकर कार्रवाई करने की मांग कर शिकायत दी थी जिसकी फाइल मानसा पुलिस के पास पहुंच चुकी है, लेकिन मानसा पुलिस ने उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मानसा पुलिस उन्हें इंसाफ देने के बजाय गैंगस्टरों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पुलिस कस्टडी से भगाया गया, उन्होंने पंजाब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने कहा के उन्हें अब तक इंसाफ नहीं दिया गया।

2022 में हुई थी हत्या - बता दें, सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह पिछली पेशी पर अपने बेटे की थार गाड़ी को अदालत में लेकर पहुंचे थे। सिद्धू मूसेवाला का 29 मई 2022 को मानसा जिले के गांव जवाहरके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने दो शूटर्स जगरूप रूप और मनु कोसा को अमृतसर जिले में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया था। वहीं इस मामले में अब नामजद लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही है।

अब सलमान खान के करीबी से करोड़ों की फिरौती और रणवीर सिंह को मिला धमकी भरा संदेश

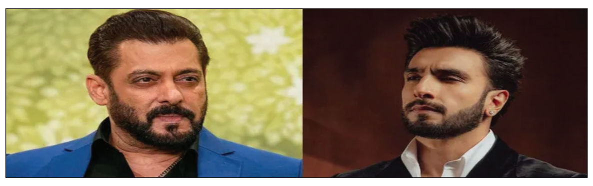

मुंबई (एजेंसी)। मायानगरी मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और अपराधी गिरोहों की सक्रियता ने फिल्म जगत में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के आवास के बाहर हुई हालिया फायरिंग की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब अभिनेता रणवीर सिंह और सलमान खान के बेहद करीबी व्यक्ति को धमकियां मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, अभिनेता रणवीर सिंह को व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी गई है, जबकि सलमान खान के एक करीबी सहयोगी को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है।

सलमान खान के करीबी को भेजे गए इस ईमेल में भेजने वाले ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य होने का दावा किया है। इस धमकी भरे पत्र में करोड़ों रुपयों की रंगदारी मांगी गई है और मांग पूरी न होने पर जान से मारने की स्पष्ट चेतावनी दी गई है। हालांकि, इस मामले में अभी तक अभिनेता या उनके सहयोगी की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस इनपुट के बाद पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। तकनीकी जांच और खुफिया जानकारी के दौरान क्राइम ब्रांच को बेहद चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग से जुड़े कुछ संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन पिछले कुछ दिनों में कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों के आसपास पाई गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गिरोह ने अपने अलग-अलग गुर्गों को इन हस्तियों की रेकी करने का काम सौंपा था। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग और अब इन नई धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सलमान खान लंबे समय से इस गिरोह के निशाने पर रहे हैं और पूर्व में उनके घर के बाहर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी भी इसी गैंग ने ली थी। पुलिस का मानना है कि इन धमकियों के पीछे मुख्य उद्देश्य बॉलीवुड से मोटी रकम की वसूली करना है। एहतियात के तौर पर मशहूर हस्तियों के आवास के आसपास सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है।

अपने बयान पर स्पष्टीकरण दें वर्ना विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का सामना करने को तैयार रहें

-संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने दी राहुल गांधी को चेतावनी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली, (ईएमएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को चेतावनी दी कि यदि राहुल गांधी शाम 5 बजे तक अपने बयान पर स्पष्टीकरण या माफी नहीं मांगते हैं तो सरकार उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। संसदीय मंत्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में ÷गलतबयानी÷ कर सदन को गुमराह किया है। उन्होंने कहा, हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रक्रिया और आचरण के स्पष्ट नियम हैं। यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो उसे पहले नोटिस देना होता है और आरोप को प्रमाणित भी करना होता है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है। रिजिजू ने सवाल उठाया, किस आधार पर? बिना नोटिस दिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सदन में बुलाकर अपने आरोपों को साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी जानबूझकर ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा, उनका भाषण आम तौर पर आरोपों से भरा होता है और उसके बाद वे सदन से चले जाते हैं। वे मंत्रियों का जवाब सुनने के लिए नहीं बैठते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता के पद पर गंभीरता का अभाव दिखता है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर संसदीय परंपराओं को आहत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र में उच्चतम मानकों और मर्यादाओं का प्रतीक है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि गांधी ने अपनी भाषा और शैली से संसदीय विमर्श का स्तर गिराया है। दरअसल, लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने इसे 'होलसेल सरेंडर' करार देते हुए कहा था कि यह समझौता बराबरी की शर्तों पर नहीं हुआ है और किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया गया है। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि सरकार ने 'भारत माता को बेच दिया।'

कांग्रेस से गठबंधन रहेगा, सत्ता-साझाकरण व्यवस्था तमिलनाडु के लिए उपयुक्त नहीं: स्टालिन

-कुछ कांग्रेसी नेताओं ने डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की उठाई थी मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बुधवार को कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। स्टालिन ने कांग्रेस जैसे डीएमके के सहयोगियों के साथ किसी भी प्रकार के साझा शासन को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं ने डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की मांग उठाई थी। स्टालिन ने कहा कि सत्ता-साझाकरण व्यवस्था तमिलनाडु के लिए उपयुक्त नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टालिन ने कहा कि शासन में हिस्सेदारी की मांग तमिलनाडु पर लागू नहीं होती। वे इसे हमसे बेहतर जानते हैं। यह नारा उन लोगों की सोची-समझी साजिश है जो हमें एकजुट नहीं देख सकते। तमिलनाडु के सीएम ने संकेत दिया कि राज्य में चुनाव होने पर कांग्रेस सहयोगी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन सौहार्दपूर्ण है। मीडिया जानबूझकर कुछ अनावश्यक धारणाएं बना रहा है।

सीएम स्टालिन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अपने संबंधों को दोनों पार्टियों के बीच निरंतर गठबंधन का एक अहम तत्व बताया। राहुल गांधी ने डीएमके नेता कनिमोझी से बातचीत करके गठबंधन में तनाव कम करने में अग्रणी भूमिका निभाई है ताकि कांग्रेस डीएमके के साथ बनी रहे। स्टालिन ने कहा कि राहुल गांधी मेरे भाई जैसे हैं, वे मेरे परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने खुद भी कई बार कहा है कि हमारा रिश्ता राजनीति से परे है। इससे पहले, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेल्वा पेरुंथगई ने भी संकेत दिया था कि डीएमके-कांग्रेस गठबंधन अंतिम रूप से तय है और औपचारिक सीट बंटवारे की बातचीत 22 फरवरी से शुरू होगी।

उन्होंने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन बेहद मजबूत गठबंधन है। जनता पहले ही यह प्रमाणित कर चुकी है कि यह सरकार बनी रहेगी। हमें लगातार जीत हासिल करने में कोई संदेह नहीं है। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। 22 तारीख को होने वाली गठबंधन बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न होगी।

ओवैसी बोले- गोरी चमड़ी वाला हमें बताएगा तेल कहां से खरीदें?

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। ओवैसी ने कहा कि 6 फरवरी को जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के सेक्शन 4 में उल्लेख है कि यदि भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखता है तो उस पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है।

सांसद ओवैसी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वह 'गोरी चमड़ी वाला' कौन होता है जो हमें बताए कि हम किससे तेल खरीद सकते हैं? हमें आजादी इसलिए मिली ताकि हम खुद तय कर सकें कि किससे तेल खरीदना है। वे कौन होते हैं हमें बताने वाले? क्या वे हमारे माता-पिता हैं जो हम पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा सकते हैं? उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा के फैसले देश के राष्ट्रीय हितों के आधार पर होने चाहिए, न कि किसी बाहरी दबाव में। ओवैसी ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की और कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जो अपने आर्थिक और रणनीतिक फैसले स्वयं लेने में सक्षम है।

इसके साथ ही ओवैसी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इंसाफ होना चाहिए और मुंबई हमलों तथा अन्य आतंकी मामलों से जुड़े आरोपियों, हाफिज सईद, मसूद अजहर और जकी-उर-रहमान लखवी को भारत लाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

15 से 25 फरवरी तक वॉरशिप का मेला, ईरान-रूस के वॉरशिप एक ही कतार में

-पहली बार फिलीपींस और यूएई के वॉरशिप इस आईएफआर में कर रहे डेब्यू

विशाखापत्तनम (एजेंसी)। विशाखापत्तनम में 15 से 25 फरवरी तक वॉरशिप का मेला लगने वाला है। सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मु का प्रेसिडेंशियल यॉट जब फ्लीट रिव्यू के लिए निकलेगा, तो दुनिया भर के वॉरशिप और नेवल पर्सनल सेल्यूट करते नजर आएंगे। रूस और अमेरिका के बीच चाहे कितनी भी खींचतान हो, लेकिन भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में दोनों ही देश अपने वॉरशिप के साथ मौजूद रहेंगे।

नौसेना के मुताबिक रूस की ओर से फ्रिगेट आरएफ़एस मार्शल शापोशनिकोव और अमेरिका की ओर से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पिंकनी हिस्सा ले रहे हैं। रूस और अमेरिका के वॉरशिप के साथ उसी कतार में ईरान का फ्रिगेट भी खड़ा दिखाई देगा। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में ईरानी नौसेना अपना फ्रिगेट डेना शामिल कर रही है। साल 2026 के आईएफआर में दुनिया के कुल 137 देशों को न्योता दिया है। 70 से ज्यादा देशों ने अपनी हिस्सेदारी की सहमति दी है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारत के तकरीबन 70 से ज्यादा वॉरशिप और सबमरीन शामिल होंगे, वहीं 20 से ज़्यादा विदेशी जंगी जहाज भी आ रहे हैं।

पहली बार फिलीपींस और यूएई के वॉरशिप इस आईएफआर में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही पहली बार जर्मनी के मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पी-8 भी फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बनेंगे। फिलीपींस का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मिगेल मालवार और यूएई नेवी का वॉरशिप अल अमारात फ्लीट रिव्यू में शामिल होंगे। फ्लाई-पास्ट में जर्मनी का लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पी-8 भी उड़ान भरेगा। समय के साथ मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ भारतीय नौसेना की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है।

बता दें 17 फरवरी 2001 को राष्ट्रपति के आर नारायणन ने आईएनएस सुकन्या से फ्लीट का निरीक्षण किया था। पहले आईएफआर में 20 देशों के 97 वॉरशिप शामिल हुए थे, जिनमें 73 भारतीय और 24 विदेशी वॉरशिप थे। आईएफआर का दूसरा संस्करण विशाखापत्तनम में साल 2016 में आयोजित किया गया था। बंगाल की खाड़ी में आयोजित इस आईएफआर में पहले से ज्यादा देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। कुल 50 देशों के तकरीबन 100 वॉरशिप पहुंचे थे। भारतीय समुद्री क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा वॉरशिप जमावड़ा था।